सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 247, नई दिल्ली । रविवार, 17 नवम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यह मत मानिए कि जीत ही सब कुछ है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हैं...

03 दिल्ली की सफ़ाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा– मेयर
06 साइबर क्राइम क्या है? प्रकार, उदाहरण और
08 अपराधियों का महिमामंडन एक चिंताजनक प्रवृत्ति

मई 2019 में जिस कारण दिल्ली सरकार ने बुराड़ी में वाहनों की जांच वापिस शुरु करवाई थी उस का निवारण किए बिना फिर से क्यों वाहनों को जांच के लिए वापिस झूलझूली भेजा गया ?

जाने पूर्ण विवरण आखिर क्यों 2019 में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने वाहनों की जांच झूलझूली वाहन जांच शाखा से वापिस बुराड़ी वाहन जांच शाखा में भेजने के आदेश जारी किए थे।

फिलहाल, दिल्ली सरकार के पास बाहरी दिल्ली के झुलझुली में केवल एक स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण केंद्र है।

संजय बाटला

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित परिवहन प्राधिकरण, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ₹भ्रष्टाचार का अड्डा₹ कहा था, पिछले वर्ष जुलाई में उनके निर्देश के बावजूद बंद होने से कोसों दूर है क्योंकि जारी एक आदेश में शहर के परिवहन विभाग ने कहा कि टैक्सियों की फिटनेस जांच का काम वापस बुराड़ी स्थित वाहन निरीक्षण इकाई (वीआईयू) को सौंप दिया गया है। डीएल1जेड श्रृंखला के अंतर्गत पंजीकृत लगभग 35,000 टैक्सियां, जिनमें नई टैक्सियां भी शामिल हैं। मंगलवार के आदेश में यह भी कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगमों से जुड़े सभी सरकारी वाहनों की जांच भी फिर से बुराड़ी केंद्र पर की जाएगी।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि वाहनों की फिटनेस को स्वचालित से मैन्युअल मोड में क्यों स्थानांतरित किया जा रहा है, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि झुलझुली केंद्र प्रतिदिन इकाई में आने वाले लगभग 400 वाहनों का भार उठाने में असमर्थ है। क्योंकि केंद्र पूरी तरह से स्वचालित है, इसलिए प्रत्येक वाहन को इकाई में प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है। नतीजतन, वाहनों की फिटनेस के लिए प्रतीक्षा समय 22 दिनों तक जा रहा है। यह एक बड़ी समस्या बन रही थी, खासकर सार्वजनिक सेवा वाहनों के मामले में। अब, कुछ श्रेणियों की कारों को बुराड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे झुलझुली का भार कम हो गया है। साथ ही बताया की नजफगढ़ से करीब 12 किलोमीटर दूर इस इलाके में कानून-व्यवस्था की समस्या भी सामने आ रही है। ₹ऐसे गुंडे हैं जो फिटनेस टेस्ट के लिए झुलझुली आने वाली टैक्सियों, बसों और भारी वाहनों से पैसे वसूलते हैं और इसी परेशानी के कारण से दो लाइसेंसिंग अधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है और कुछ गुंडों के खिलाफ परिवहन विभाग ने दो एफआईआर भी दर्ज की हैं और इसी कारणों से बुराड़ी की तरह झुलझुली में भी दलाली की संस्कृति पनप रही है।

37 एकड़ में फैले बुराड़ी आरटीओ में दो इकाइयां हैं – ऑटो-रिक्शा इकाई (एआरयू) और वाणिज्यिक वाहन निरीक्षण इकाई (वीआईयू)।

जुलाई 2018 में मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा बुराड़ी वाहन जांच शाखा में निरीक्षण के बाद सरकार ने बुराड़ी के दोनों वाहन जांच शाखाओं को बंद करने का फैसला किया था। सरकार ने तब 37 एकड़ के भूखंड पर अत्याधुनिक प्रशिक्षण-सह-परीक्षण संस्थान बनाने की योजना तैयार की थी, जिसे बाद में मई 2019 को रुकवा दिया गया था। यहां तक बुराड़ी के एआर.यू. आटो वाहन जांच शाखा को बंद कर शहर भर के 13 आर.टी.ओ. में विकेंद्रीकृत कर दिया गया था। नवंबर 2019 में स्वयं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विभाग को बुराड़ी ए.आर.यू. आटो वाहन जांच शाखा को फिर से खोलने का निर्देश जारी किया था। परिवहन विभाग द्वारा तैयार

की गई एक रिपोर्ट में कहा गया था की अकेले एआरयू इकाई में 13 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओएस) की तुलना में लगभग दोगुनी भीड़ होती है। ऑटो इकाई के उस समय पदस्थ लाइसेंसिंग अधिकारी ने बताया था की उनके पास प्रतिदिन 500 से अधिक ऑटो-रिक्शा फिटनेस परीक्षण के लिए आते हैं। सितंबर से ऑटो-रिक्शा के लिए विशेष रूप से खोले गए आरटीओ में प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या घटकर मात्र 50 रह गई थी।

अब सवाल यह उठता है की दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार जब 2018 से इस बात को जानते थे की झूलझूली वाहन जांच शाखा में किसी भी हालात में दिल्ली में पंजीकृत व्यवसायिक श्रेणी के वाहनों की जांच समयानुसार सम्भव नहीं है और झूलझूली वाहन जांच शाखा के पास क़ानून व्यवस्था की भयंकर समस्या है और परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी उससे बचे हुए नहीं हैं तो क्यों वाहनों को जबरदस्ती फिर से पूर्व से अब तक उठ रही समस्याओं के समाधान किए बिना भेजने के आदेश जारी किए।

ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है की जानते बुझते हुए व्यवसायिक वाहन मालिकों और चालकों की जान जोखिम में डालने और व्यवसायिक वाहनों की जांच में बाधा डलवाने के पीछे कुछ तो छुपा हुआ सत्य अवश्य है जिसकी जांच आवश्यक है।

ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है की तत्काल प्रभाव से वाहनों की जांच वापिस बुराड़ी वाहन जांच शाखा में शुरू करने की आदेश जारी किए जाए और इस बाबत बिना समस्याओं के समाधान किए वाहनों को जबरदस्ती झूलझूली भेजने के आदेश जारी करने वाले

क्या दिल्ली में होगी कृत्रिम बारिश? केंद्र के साथ-साथ IIT दिल्ली भी नहीं दे रहा कोई जवाब

नई दिल्ली। प्रदूषण से जंग में इस बार भी दिल्ली में कृत्रिम वर्षा होने की संभावना नहीं के बराबर ही लग रही है। वजह, दिल्ली सरकार के अनुरोध पर केंद्र तो कोई कार्यवाही नहीं ही कर रहा है, इसका सुझाव देनेवाला आईआईटी कानपुर भी कोई जवाब नहीं दे रहा। आलम यह है कि सरकार इन दोनों से ही सहयोग मिलने का इंतजार कर रही है।

जानकारी के मुताबिक पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को अब तक तीन पत्र लिखे हैं। तीनों पत्रों में यही अनुरोध किया गया है कि एक्यूआई के 'गंभीर' या 'बहुत गंभीर' हो जाने की स्थिति में कृत्रिम वर्षा के जरिए हालात पर काबू पाया जा सके, इसके लिए सभी संबंधित विभागों की एक बैठक रखी जाए, लेकिन अभी तक यथास्थिति ही बनी हुई है।

आईआईटी कानपुर से कृत्रिम वर्षा कराने का प्रस्ताव

इसी कड़ी में पर्यावरण विभाग ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए पिछले महीने आईआईटी कानपुर से कृत्रिम वर्षा कराने को लेकर एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने को कहा था, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता अमित गुप्ता द्वारा लगाई गई एक आरटीआई के जवाब में पर्यावरण विभाग ने स्वयं स्वीकार किया है कि डेढ़ माह बाद भी कोई प्रस्ताव नहीं मिला पर्यावरण विभाग का कहना है कि आईआईटी कानपुर को सात अक्टूबर को इस निमित्त पत्र लिखा गया था। तभी से उनके जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।

क्लाउड सीडिंग का विस्तृत रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विशेषज्ञ कृत्रिम वर्षा के उपाय को बहुत व्यावहारिक नहीं मानते। मशहूर पर्यावरणविद और सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण का कहना है कि सिर्फ वर्षा से प्रदूषण खत्म नहीं होता। वर्षा के साथ हवा भी चलना बहुत जरूरी है। इसलिए कृत्रिम वर्षा बिल्कुल बेमानी है। उन्होंने यह कहा कि क्लाउड सीडिंग विज्ञान का विस्तृत रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरोजिनी नगर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो 'सखी डिपो' का उद्घाटन किया

सुषमा रानी

नयी दिल्ली। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरोजिनी नगर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो 'सखी डिपो' का उद्घाटन किया। विश्व स्तर पर यह अपनी तरह का पहला अभूतपूर्व पहल है। सखी डिपो में ड्राइवर और कंडक्टर सहित सभी कर्मचारी महिलाएँ ही होंगी।

उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, कैलाश गहलोत ने महिला कार्यबल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहाः

"'सखी डिपो' न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान परिवहन क्षेत्र में महिलाओं द्वारा सभी बाधाओं को तोड़ने का एक प्रमाण भी है। यह डिपो बस शुरुआत है; हमारा लक्ष्य 'सखी' पहल के तहत दिल्ली भर में ऐसे कई डिपो स्थापित करना है, जो पूरे देश में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करें और उन्हें प्रेरित करें।"

'सखी डिपो' की विशेषताएं

सरोजिनी नगर सखी डिपो में कुल 223 महिला कार्यबल हैं, जिनमें 89 ड्राइवर और 134 कंडक्टर शामिल हैं। डिपो 70 बसों का बेड़ा संचालित करता है, जिसमें 40 वातानुकूलित (एसी) और 30 गैर-एसी बसें शामिल हैं, जो दिल्ली भर में 17 मार्गों पर सेवा

प्रदान करती हैं।

'सखी डिपो' तक का सफ़र

'सखी डिपो' की स्थापना परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का पुराना सपना था। हालाँकि, इस सपने को हकीकत में बदलने का सफर कई चुनौतियों से भरा रहा।

एक महत्वपूर्ण बाधा महिला ड्राइवरों के लिए ऊंचाई की आवश्यकता थी। 159 सेमी की मूल न्यूनतम ऊंचाई की आवश्यकता के कारण कई महिलाएँ ड्राइवर नहीं बन पा रही थीं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के प्रयासों से फरवरी 2022 में ऊंचाई की आवश्यकता को घटाकर 153 सेमी कर दिया गया। महिला ड्राइवरों की सुविधा के लिए, बसों को पावर स्टीयरिंग, समायोज्य सीटों और स्टीयरिंग विकल्पों से सुसज्जित किया गया।

भारी मोटर वाहन (एचएमवी) लाइसेंस प्राप्त करने की चुनौती से निपटने के लिए, दिल्ली सरकार ने मिशन परिवर्तन शुरू करने के लिए अप्रैल 2022 में अशोक लीलैंड के साथ साझेदारी की। इस पहल के अन्तर्गत दिल्ली सरकार और अशोक लिलैंड द्वारा महिला ड्राइवरों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हुई।

ट्रेनिंग के बाद 11 महिला ड्राइवरों का पहला बैच अगस्त 2022 में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) में शामिल हो गया। समय के साथ, महिला ड्राइवरों की संख्या बढ़ती गई, वर्तमान मे 89 महिला ड्राइवर डीटीसी में बस चला रहीं हैं।

'सखी डिपो' का ऐतिहासिक महत्व

पहले सरोजिनी नगर डिपो के नाम से जाना जाने वाला सखी डिपो दिल्ली के परिवहन इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अप्रैल 1954 में उद्घाटन किया गया यह दिल्ली का पहला बस डिपो था। महान स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू के नाम पर बनाया गया यह डिपो प्रगति और सशक्तिकरण का प्रतीक है।

दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली की पहली महिला बस ड्राइवर वंकदावथ सरिता ने 10 अप्रैल, 2015 को डीटीसी जॉइन किया और सरोजिनी नगर डिपो से अपनी यात्रा शुरू की।

'सखी' पहल का भविष्य

सखी डिपो दिल्ली भर में महिला डिपो बनाने की व्यापक दृष्टि में पहला कदम है। ये डिपो 'सखी' पहल के अंतर्गत आएंगे, जिसका उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं को सशक्त बनाना और सार्वजनिक परिवहन में समान अवसर प्रदान करना है।

'सखी डिपो' के लॉन्च के साथ, दिल्ली ने न केवल लैंगिक समानता की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया है, बल्कि दुनिया भर

दिल्ली के कार चालकों पर 1 और बिना PUCC वालों पर 4.8 करोड़ का जुर्माना, ग्रेप-3 के नियम तोड़ने पर 5300 वाहनों का चालान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 3 लागू होने के बाद 550 वाहनों के चालान काटे हैं। इनमें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन शामिल हैं। इन पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) न होने के लिए 4855 वाहनों का चालान काटा गया है। इन पर 4 .8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 3 लागू होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 550 वाहनों के चालान काटे हैं। इनमें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन हैं। इन पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

पुलिस ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) न होने के लिए 4,855 वाहनों का चालान काटा। इन पर 4.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने गुरुवार को दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया था, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में एक्यूआई 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। इसके तहत वाहनों पर प्रतिबंध लगाए थे।

कितना लगता है जुर्माना

दिल्ली ट्रैफिक नियमों के अनुसार, वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र न होने पर वाहन चालकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इन चालानों को कोर्ट से जारी किया जाता है। ग्रेप-3 के अनुसार, निजी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर ये सड़क पर चलते मिलते हैं तो 20 हजार का जुर्माना लगाया जाता है।

एनसीआर के शहरों से दिल्ली आने वाली डीजल और पेट्रोल बसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

कहां कितने चालान हुए

दिल्ली पुलिस के अनुसार, शहर के पूर्वी, मध्य और उत्तरी रेंज में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के लिए कुल 293 चालान जारी किए हैं। पीयूसीसी प्रमाणपत्र न होने पर कुल 2,404 चालान जारी किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली रेंज ने 63 चालान जारी किए हैं, जबकि पश्चिमी रेंज ने 73 और दक्षिणी रेंज ने 121 चालान जारी किए हैं। नई दिल्ली में 322, दक्षिणी में 894 और पश्चिमी रेंज में 1,235 चालान जारी हुए हैं।

बॉर्डर से वाहनों को लौटाया वापस

पुलिस उपायुक्त (यातायात) राजीव कुमार रावल ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को यातायात पुलिस की तीनों रेंज में करीब 3,000 वाहनों की जांच की। उन्होंने बताया कि बॉर्डर इलाकों में जांच तेज कर दी है। बसों की भी जांच की जा रही है। प्रतिबंधित वाहनों को लौटा दिया जा रहा है। ऐसे लगभग 300 वाहनों को वापस लौटाया है। बिना पीयूसीसी के चलने वाले वाहनों के चालान कर रहे हैं।

हर माह दो लाख से ज्यादा लोगों का यातायात पुलिस ने काटा चालान

दिल्ली की यातायात पुलिस 75 तरह के यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में चालान काटती हैं, इनमें किसी भी नियम का उल्लंघन पाए जाने पर वाहन चालकों का चालान कट सकता है। क्षतिग्रस्त हेलमेट, बिना बेल्ट के हेलमेट पहनने, बेल्ट टाइट से न बांधने, धूम्रपान करते हुए वाहन चलाने, वाहन का हार्न खराब होने, आपातकालीन वाहनों को साइड न देने आदि कई मामलों में चालान कटने की जानकारी लोगों को नहीं है।

ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बीते दस माह में विभिन्न नियमों के उल्लंघन करने पर 25 लाख से अधिक लोगों के चालान काटे गए। यानी हर माह दो लाख से अधिक लोगों के चालान काटे गए।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

पांडवों ने एक रात में किया था एकविरा देवी मंदिर का निर्माण, जानिए पौराणिक कथा

महाभारत काल में पांडवों ने धर्म के रास्ते पर चलते हुए बुरे और संघर्ष भरे दिनों का सामना किया था। वहीं पांडवों ने सत्य की जीत और बुराई की हार के लिए भगवान श्रीकृष्ण के अलावा कई अन्य देवी-देवताओं की सहायता ली थी।

महाभारत काल की कई कहानियां हम सभी ने पढ़ व सुन रखी हैं। महाभारत से मनुष्य को कई सीखें भी मिलती हैं। जैसे महाभारत काल में पांडवों ने धर्म के रास्ते पर चलते हुए बुरे और संघर्ष भरे दिनों का सामना किया था। इन दिनों से निकलने के लिए पांडवों ने काफी संघर्ष भी किया था। वहीं पांडवों ने सत्य की जीत और बुराई की हार के लिए भगवान श्रीकृष्ण के अलावा कई अन्य देवी-देवताओं की सहायता ली थी। पांडवों ने संघर्ष भरे दिनों से मुक्ति पाने और मां की कृपा पाने के लिए देवी एकविरा की कठोर तपस्या की थी। देवी एकविरा की कृपा से पांडवों के अज्ञातवास के दिन आसान हो गए थे। तो ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको देवी एकविरा मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं।

कहां हैं एकविरा देवी मंदिर

बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई से करीब 100 किमी दूर लोनावला स्थित है। लोनावला प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत जगह है। यहां पर कार्ला गुफाएं हैं, जहां एकविरा देवी का प्राचीन मंदिर है। पौराणिक मान्यता है कि यह मंदिर कई सालों पुराना है। जिन गुफाओं के ठीक बगल में एकविरा देवी की पूजा की जाती है, उसे कभी बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता था।

एक रात में बना था ये मंदिर

एकविरा देवी की चुनौती को स्वीकार करते हुए पांडवों ने एक रात में लोनावला पहाड़ियों के बीच एकविरा देवी के मंदिर का निर्माण कर दिया। जब मंदिर का निर्माण हो गया, तो पांडवों ने मां का आह्वान किया और उन्हें दर्शन देने के लिए कहा। पांडवों का आह्वान सुनकर एकविरा देवी ने उन्हें दर्शन दिया और उनको वरदान दिया कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों को कोई भी पहचान नहीं पाएगा। जिससे उनका अज्ञातवास सरलता से पूरा हो जाएगा।

मां ने पांडवों को दिए थे दर्शन

पौराणिक कहानी के अनुसार, महाभारत काल के दौरान जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ, तो पांडव भाई दुखी होकर अपने साथ हुए अन्याय की बातें कर रहे थे। तभी एकविरा देवी ने पहाड़ियों से उनकी बातें सुनीं और उनका मन पीड़ा से भर उठा। ऐसे में एकविरा देवी ने पांडवों को कष्ट से निकालने के लिए उनकी सहायता भी की। देवी ने कहा कि वह पांडवों की नियति को नहीं बदल सकती हैं, क्योंकि तुम सभी ने एक महान कार्य को पूरा करने के लिए जन्म लिया है। तुम्हारी वजह से युग परिवर्तन होगा। ऐसे में मैं तुम्हें इन संघर्ष भरे दिन से निकालने के लिए तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी।

पांडवों की ली परीक्षा

देवी एकविरी की बात सुनकर पांडव मां के आगे नतमस्तक हो गए। तब देवी ने पांडवों की परीक्षा लेने के लिए कहा कि यदि वह अपने अज्ञातवास को सरल बनाता चाहते हैं, तो उन्हें इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करना होगा। लेकिन मंदिर का निर्माण अगले दिन सुबह होने से पहले हो जाए। यानी की मंदिर एक रात में बन जाना चाहिए। माता की बात सुनकर पांडव समझ गए कि देवी एकविरा उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति देखना चाहती हैं।

ऐसे पहुंचे मंदिर

एकविरा देवी मंदिर कई नामों से जाना जाता है। कई लोग एकविरा देवी को रेणुका देवी भी कहते हैं। ऐसे में अगर आप भी एकविरा देवी मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो बता दें कि यह पूणे से 60 किमी और मुंबई से 100 किमी दूर है। वहीं लोनावला से इस मंदिर की दूरी करीब 10 किमी है।

विक्रांत मैसी ने फिर किया कमाल, गोधरा ट्रेन की कहानी को संवेदनशीलता और तथ्यों के साथ पेश किया

'द साबरमती रिपोर्ट' 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने से 59 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। फिल्म एक रिपोर्टर के जरिए इस बात पर प्रकाश डालती है कि यह एक दुखद दुर्घटना थी या कोई भयावह साजिश।

'12वीं फेल' के बाद, फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर क्रिटिक 2023 विजेता विक्रांत मैसी अपनी फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' के साथ बड़े पर्दे पर वापस आ गए हैं। यह फिल्म कई कारणों से लंबे समय से चर्चा में है, जैसे निर्देशक में बदलाव, रिलीज की तारीख में देरी और ट्रेलर की प्रतिक्रियाएं। लेकिन अब यह फिल्म सिनेमाघरों में आ गई है, जिसमें विक्रांत मैसी के साथ रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना भी हैं। हाल ही में 'सिंघम अगेन' और 'भूल भुलैया 3' जैसी घटिया दिवाली रिलीज के साथ, 'द साबरमती रिपोर्ट' अलग है, कहानी के मामले में बेहतर है, और दर्शकों को सबसे घातक भारतीय दंगों में से एक के दौरान खोई गई निर्दोष जिंदगियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। निर्माता एकता कपूर और निर्देशक धीरज सरना की 'द साबरमती रिपोर्ट' का दावा है कि इसने भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की कहानी को पर्दे पर उतारा है, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा, पढ़ा और सुना जा चुका है, लेकिन क्या यह सब सच है? निर्माताओं ने इस घटना में एक नया पहलू जोड़ने की कोशिश की है। फिल्म भारतीय मीडिया घरानों की भागीदारी और उसके पत्रकारों की दुविधा को उजागर करती है।

कहानी

'द साबरमती रिपोर्ट' 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने से 59 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। फिल्म एक रिपोर्टर के जरिए इस बात पर प्रकाश डालती है कि यह एक दुखद दुर्घटना थी या कोई भयावह साजिश। हालांकि, जो लोग यह सोच रहे हैं कि इस फिल्म में गुजरात की घटना पर पहले बनी फिल्मों की तरह कोई पुराना कथानक होगा, तो शायद आप गलत हैं। निर्माताओं ने साबरमती एक्सप्रेस की घटना को लेकर एक साहसिक दृष्टिकोण अपनाया है। फिल्म में हिंदी भाषी पत्रकारों और पश्चिमी मीडिया के बीच वैचारिक टकराव को भी दिखाया गया है, जो 'द साबरमती रिपोर्ट' को और भी दिलचस्प और वास्तविक बनाता है। भारतीय इतिहास में रुचि रखने वालों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए।

कहानी की शुरुआत इस रेल दुर्घटना की सच्चाई जानने की जद्दोजहद से होती है, जिसमें हिंदी भाषी पत्रकार समर कुमार (विक्रांत मैसी) और अंग्रेजी पत्रकार मनिका राजपुरोहित के बीच सच और झूठ के बीच संघर्ष दिखाया गया है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब महिला पत्रकार अमृता गिल (राशि खन्ना) की एंट्री होती है और वह समर के अधूरे प्रयास को नए पंख देने के लिए इस पूरी घटना की जांच करती है। क्या समर और अमृता इसमें सफल होते हैं? इसके लिए आपको यह फिल्म देखनी होगी।

अभिनय

'द साबरमती रिपोर्ट' में कलाकारों का अभिनय सराहनीय है। पत्रकारों की भूमिका निभाने वाले विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा ने अपने अभिनय से कहानी को और भी गहरा बना दिया है। विक्रांत जैसे अभिनेता के लिए, जिन्होंने '12वीं फेल', 'सेक्टर 36' और 'डेथ इन द गंज' जैसी कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिकाएँ निभाई हैं, 'द साबरमती रिपोर्ट' के साथ यह और भी बेहतर हो जाता है। इस फिल्म में उनका अभिनय पानी की तरह है; यह बहता है और शांत प्रभाव डालता है। राशि ने अपने किरदार में एक खास आकर्षण जोड़ा है, वहीं रिद्धि ने अपने प्रभावशाली अभिनय से सबका मन मोह लिया है। वह एक बॉस लेडी के किरदार में पूरी तरह से रम गई हैं और उसके साथ न्याय करती हैं।

लेखन और निर्देशन

एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के मशहूर टीवी शो 'कुटुंब' में यश की भूमिका में नजर आने वाले अभिनेता धीरज सरना ने 'द साबरमती रिपोर्ट' का निर्देशन किया है। जहां निर्माताओं ने नानावटी-मेहता आयोग के निष्कर्षों पर कायम रहते हुए भी सरन के प्रयासों में अनुभव की कमी है; इसका सबूत आप फिल्म के कुछ दृश्यों को देखकर आसानी से देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर, इस गंभीर मुद्दे को पर्दे पर उतारने का उनका प्रयास अच्छा रहा है। इसके अलावा, लेखन में खामियों को अच्छे अभिनय और बैकग्राउंड स्कोर द्वारा उचित रूप से कवर किया गया है।

ट्रेन के जलने जैसे दृश्यों में वीएफएक्स तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सिनेमैटोग्राफी थोड़ी ठंडी लगती है। बतौर निर्माता एकता कपूर ने दर्शकों को सिनेमाघरों में पैसे वसूल मनोरंजन देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिल्म का खामोश हिस्सा इसकी लेखनी है। इसके अलावा, बीच-बीच में फिल्म थोड़ी सी पटरी से उतरती हुई नजर आती है, क्योंकि गुजरात दंगों से ज्यादा 'द साबरमती रिपोर्ट' दो लीग के पत्रकारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन जाती है, लेकिन यह आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी।

इन बीमारियों के होने पर पड़ सकते हैं मिर्गी के दौरे, जानिए कारण और लक्षण

मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसॉर्डर है। हार्ट से जुड़ी बीमारियां होने पर भी व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी हो सकती है। ऐसे में आज हम आपको इस बीमारी के कारण, लक्षण और इससे बचाव के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं।

मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसॉर्डर है, इस स्थिति में दिमाग के अंदर असामान्य तरंगे उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति को बार-बार दौरा पड़ने लगता है। जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो व्यक्ति की दिमागी और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। दौरा पड़ने पर कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग लड़खड़ाने लगते हैं। अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज नहीं कराया गया, तो यह बीमारी खतरनाक रूप ले सकती है।

एक्सपर्ट की मानें, तो कई बार पीड़ित व्यक्तियों में इस बीमारी का सही कारण पता लगा पाना काफी मुश्किल होता है। कुछ लोगों को गंभीर बीमारी के बाद मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। तो वहीं कुछ लोगों के दिमाग पर गहरी चोट लगने या फिर चोट के निशान पड़ने पर भी दौरे पड़ सकते हैं। हार्ट से जुड़ी बीमारियां होने पर भी व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी हो सकती है। ऐसे में आज हम आपको इस बीमारी के कारण, लक्षण और इससे बचाव के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं।

डॉक्टर्स की मानें तो कई बार रोगियों में मिर्गी के सही कारणों का पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को किसी गंभीर बीमारी के बाद मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। दिमाग में गंभीर चोट लगने या चोट के निशान रह जाने पर भी लोगों को मिर्गी का दौरे पड़ने लगते है। कार्डियोवस्क्युलर डिसीज यानि हार्ट से जुड़ी बीमारियां होने पर भी इंसान को मिर्गी की बीमारी हो सकती है। कुछ मामलों में तेज बुखार भी दिमाग पर असर डाल सकता है।

क्या हैं मिर्गी के लक्षण

मिर्गी से दो तरह के दौरे पड़ते हैं। जिनमें से एक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होता है। इस कंडीशन में व्यक्ति के पूरे दिमाग में दौरा पड़ता है। यह दौरा तब तक होता है, जब तक की पीड़ित बेहोश न हो जाए। तो वहीं दूसरा फोकल एप्लेकिसी होता है। इस कंडीशन में दिमाग के कुछ हिस्से में इलेक्ट्रिकल तरंगे दौड़ती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति के सूंघने या चखने की शक्ति में बदलाव होता है और शरीर में मरोड़ आने लगता है। इसमें देखने, सुनने या फिर फील करने की क्षमता खो जाती है।

मिर्गी के कारण

ब्रेन स्ट्रोक होने पर व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ने का खतरा होता है।

जब ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तब भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है।

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में फोड़ा होने पर भी मिर्गी का खतरा हो सकता है।

उम्र बढ़ने पर जिन लोगों को अल्जाइमर या डेमेंशिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं, उनको भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं।

एड्स या मैनिंजाइटिस की समस्या से पीड़ित व्यक्ति भी इस बीमारी की चपेट में आ सकता है।

कई बार नशीली दवाओं का अधिक सेवन करने और जेनेटिक कारणों से भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं।

ऐसे करें बचाव

मिर्गी की समस्या से बचने के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का नियमित रूप से सेवन करते रहें।

हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं।

रोजाना व्यायाम करें।

तनाव और चिंता कम करें।

पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है।

संतुलित और पौष्टिक खाना खाएं।

शराब और नशीली चीजों से दूरी बनाएं।

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

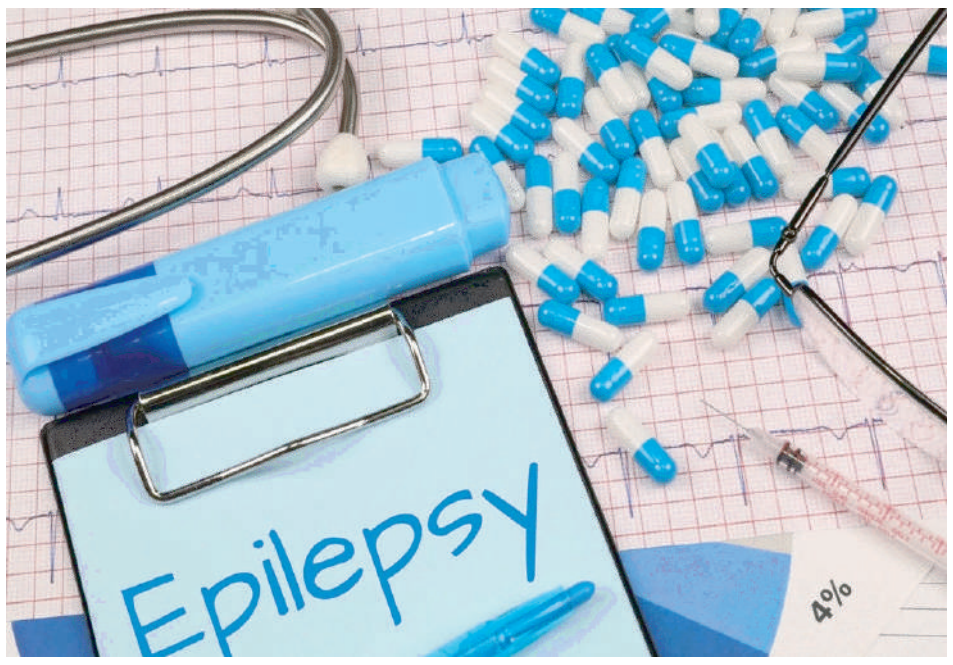

कच्चे केले से मिनटों में तैयार करें क्रिस्पी ट्विस्टर, नोट कर लें रेसिपी

क्या आप जानते हैं कि आप केला की सब्जी से लेकर चिप्स तक बनाकर खा सकते हैं। नारियल के तेल में तले हुए केले के चिप्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं। खासकर यह चिप्स डाइटिंग करने वाली लड़कियां और व्रत के दौरान भी खाना पसंद किया जाता है।

केला स्वाद के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। यही कारण है कि लोग केला का कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कच्चे केले की कोई डिश बनाते हैं, तो कुछ लोग इसके व्यंजन या ड्रिंक्स भी बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप केला की सब्जी से लेकर चिप्स तक बनाकर खा सकते हैं। नारियल के तेल में तले हुए केले के चिप्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं।

खासकर यह चिप्स डाइटिंग करने वाली लड़कियां और व्रत के दौरान भी खाना पसंद किया जाता है। हालांकि व्रत वाली चिप्स सादी होती है, तो वहीं नॉर्मल दिनों में हम थोड़ा चटपटी चिप्स खाना पसंद करते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको केले की चिप्स बनाने की रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं।

सामग्री

कच्चे केले- 2 (कटे हुए)

स्टिक- 1

पेरी पेरी मसाला- एक चम्मच

कॉर्न फ्लोर- 1 कप

मैदा- आधा कप

नमक- स्वादानुसार

तेल- फ्राइंग

कच्चे केले के ट्विस्टर

सबसे पहले सभी सामग्रियों को तैयार कर लें। फिर केले के छिलके उतारकर इसे बीच से काटते जाएं और अंत में स्टिक के अंदर लगा दें।

केले के आकार की स्प्रिंग होना चाहिए। फिर एक बाउल में 4 गिलास पानी और एक चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें।

अब स्प्रिंग किए हुए केले को करीब 10 मिनट तक पानी में रहने दें।

एक बाउल में आधा कप मैदा, 2 बड़े चम्मच पेरी-पेरी मसाला और एक कप कॉर्नफ्लोर डालकर मिक्स कर लें।

इसके बाद इसमें पानी डालकर पेस्ट बना लें और फिर स्प्रिंग केले को इसमें डालकर अच्छे से भिगो दें।

अब कड़ाही में तेल गर्म करें और कोटिंग किए हुए केले को गोल्डल और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें।

जब यह फ्राई हो जाएं, तो एक प्लेट में इन्हें निकाल लें। अब आप इनको मेयोनीज और पेरी-पेरी मसाला डालकर गार्निश कर सर्व करें।

भारत में स्मार्टफोन मार्केट की 5.6 प्रतिशत की ग्रोथ रिकॉर्ड, ऐपल फोन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

दरअसल, मार्केट ने लगातार पांचवीं तिमाही में ग्रोथ दर्ज की है। 2024 की तीसरी तिमाही में मार्केट में 5 .6 प्रतिशत की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई। यहां पर 4 .6 करोड़ स्मार्टफोन यूनिट्स की शिपमेंट की गई। Apple ने यहां सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी ने किसी तिमाही में अब तक की सबसे ज्यादा शिपमेंट्स की हैं।

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, मार्केट ने लगातार पांचवीं तिमाही में ग्रोथ दर्ज की है। 2024 की तीसरी तिमाही में मार्केट में 5.6 प्रतिशत की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई। यहां पर 4.6 करोड़ स्मार्टफोन यूनिट्स की शिपमेंट की गई। Apple ने यहां सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी ने किसी तिमाही में अब तक की सबसे ज्यादा शिपमेंट्स की हैं। रिपोर्ट के अनुसार एपल ने 40 लाख स्मार्टफोन भारत में पिछली तिमाही में बेचे हैं। IDC की वर्ल्डवाइड क्वार्टरली मोबाइल फोन ट्रैकर रिपोर्ट में ये बात कही गई है।

भारत में स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियों समेत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी ग्राहकों को पोन फेलेक्सिबल तरीके से खरीदने का ऑप्शन दे रहे हैं। इसमें बड़े डिस्काउंट्स, फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग, एक्सटेंडेट वारंटी, कैशबैक ऑफर आदि शामिल हैं जिससे ग्राहकों फोन खरीदने के कई विकल्प मिल जाते हैं। IDC Aisa Pacific में सीनियर रिसर्च मैनेजर उपासना जोशी के अनुसार नए 5G स्मार्टफोन के लॉन्च से भी मार्केट ग्रोथ बढ़ी है। ऐपल, सैमसंग जैसे दिग्गज स्मार्टफोन मेकर ऑनलाइन सेल्स के दौरान अपने फ्लैगशिप मॉडल्स को अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ उपलब्ध करवा रहे हैं।

वहीं एपल ने भारत में 2024 की तीसरी तिमाही में सबसे ज्यादा फोन बेचे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने 2024 Q3 में 40 लाख स्मार्टफोन की ब्रिकी की। इसमें सबसे सेल कंपनी के आईफोन 15 और आईफोन 13 मॉडल्स की हुई। कंपनी ने यहां सैमसंग को पीछे छोड़ दिया। ऐपल ने जहां 28.7 प्रतिशत शेयर हासिल किया, वहीं सैमसंग 15.2 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ पीछे रह गई। वीवो, ओप्पो जैसे ब्राड्स तीसरी तिमाही में भी मार्केट को लीड कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार अपनी लापरवाही माने और पीड़ित परिवारों को कम से कम 1 करोड़ का मुआवज़ा दे- संजय सिंह

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित मेडिकल कॉलेज में आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत की घटना पर गहरा शोक जताया करते हुए इसे लापरवाही से की गई हत्या करार दिया है। ₹आप₹ सांसद संजय सिंह ने इसे लापरवाही पूर्ण हत्या बताया है और परिवार के लिए एक एक करोड़ रुपए मुआवजे की देने मांग की है। संजय सिंह का कहना है कि जिस आईसीयू में यह हादसा हुआ, उसे योगी सरकार ने चंद महीने पहले ही वर्ल्ड क्लास बताकर शुरू किया था। जानकारी मिली है कि अस्पताल में आग बुझाने वाले यंत्र 2020 में ही काम करना बंद कर चुके थे, इसके बावजूद वो वहां पड़े थे। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी लापरवाही माने और परिवारों को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दे। साथ ही, मुख्यमंत्री योगी को इस दुख और आपदा की घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए और यह जांच करनी चाहिए कि इसके लिए कौन लोग दोषी हैं?

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि झांसी मेडिकल कॉलेज में बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें अब तक 10 बच्चों की जान जा चुकी है। जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक लगभग 37 बच्चे झुलसे हुए हैं और जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। यही

आईसीयू वार्ड है, जिसे वर्ल्ड क्लास सुविधा बताकर 8 महीने पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रचारित किया था और बहुत ढोल पीटा था कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधा शुरू की गई है। यहां तक जानकारी मिली है कि जो आग बुझाने वाले यंत्र अस्पताल के अंदर लगे हुए थे, वे 2020 से ही काम करना बंद कर चुके थे और एक्सपायर हो गए थे। इसके बावजूद वे यंत्र वहां पड़े हुए थे। तो आप यह कल्पना कर सकते हैं कि लापरवाही की पराकाष्ठा क्या है। आप यह भी समझ सकते हैं कि किस तरह उत्तर प्रदेश में लोगों, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों को हर बात पर नफरत की आग में झोंका जाता है और हर मुद्दे पर उन्हें बांटने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो सुविधाएं आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, उनका कितना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है, और उन्हें किस तरह बर्बाद किया जा रहा है, यह इस घटना से साबित होता है।

संजय सिंह ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि वह अपनी निर्दयता छोड़ें, अपनी लापरवाही मानें और इन परिवारों के साथ खड़ी हो। ये बच्चे पूरी जिंदगी जी सकते थे, अपने घर-परिवार, देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आज उनका परिवार सड़क पर खड़ा है। इन बच्चों के परिवारों को कम से कम एक करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। योगी जी हर बात पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, इस दुख और आपदा की घड़ी में उन्हें उन परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्हें यह जांच करनी चाहिए कि इसके लिए कौन लोग दोषी हैं, और किनकी लापरवाही के कारण यह सब कुछ हुआ। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह बच्चों की लापरवाही पूर्ण हत्या का मामला है।

उन्होंने कहा कि मैं फिर से यह मांग करूंगा कि इन परिवारों को मुआवजे, सहानुभूति और उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। योगी सरकार को यह काम तत्काल करना चाहिए और इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। अगर हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होगी, तो शायद निष्पक्ष जांच हो पाएगी, वरना हमने देखा है कि योगी सरकार की पेपर लीक और कोरोना काल के समय हुई पिछली जांचें मात्र एक औपचारिकता साबित हुई हैं, और उनका कोई नतीजा नहीं निकला। आज वक्त है कि हम सब सोचें कि भाजपा की सरकार बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के मुद्दों पर लोगों के साथ क्या कर रही है।

युवाओं को रोजगार मिलने से होगी देश की तरक्की : डॉ. मणीन्द्र जैन

जैन ने कहा कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि गरीबी के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य ' जीओ और जीने दो' का है इसी के तहत हम हर भारतवासी को स्वावलंबी और समृद्ध बनाने का लक्ष्य तैयार कर रहे हैं। देश के राजनीति में युवाओं और अच्छे लोगों को प्रवेश करा गिरते राजनीतिक माहौल ठीक किया जा सकता है।

नई दिल्ली । धारा 370 को हटाये जाने का फायदा तब होगा जब कश्मीर से भगाये गए कश्मीरी पंडितों को फिर से वहां बुलाया जाय और उनकी जमीन दिलवाई जाए। यह बात वीर जनशक्ति पार्टी (वीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मणीन्द्र जैन ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कांफ्रेस में कही। उन्होंने कहाकि पार्टी अगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी।

दिल्ली प्रदेश के सदस्य पवन शर्मा ने एमडीसी के 80 फीसद बच्चों को देखने की समस्या है। यह एक गंभीर समस्या है, जिसका समाधान किया जाना चाहिए। जिनके कंधे पर भविष्य की जिम्मेदारी पड़ने वाली है अगर उसकी नजर ही कमजोर होगी तो फिर देश का भविष्य क्या होगा। जैन ने कहाकि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि गरीबी के आधार पर होनी चाहिए। डॉ. मणीन्द्र जैन ने कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य ' जीओ और जीने दो' का है, इसी के तहत हम हर भारतवासी को स्वावलंबी और समृद्ध बनाने का लक्ष्य तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के राजनीति में युवाओं और अच्छे लोगों को प्रवेश कराके ही वर्तमान में गिरते राजनीतिक स्तर के माहौल ठीक किया जा सकता है। इस अवसर पर पार्टी की ओर से संकल्प पत्र भी जारी किया गया। जिसका स्लोगन है 'करने कराने के लिए कटिबद्ध है, एवं वचनवद्ध है' ।

जैन के कहा कि हम लोग गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाने की योजना पर काम कर है। उन्होंने कहा कि जब युवाओं को रोजगार मिलेगा तभी देश प्रगति करेगी। हमारा किसी भी पार्टी से कोई बैर नहीं है। हमारा एक ही मकसद है देश की प्रगति और सनातन धर्म की रक्षा। प्रेस कांफ्रेस में राष्ट्रीय सचिव धरणोन्द्र कुमार जैन , महेंद्र तुरखिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सुकृति जैन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, विशन सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, एच.एन.शर्मा राष्ट्रीय मार्गदशर्क, विपिन गुप्ता राष्ट्रीय मार्गदशर्क, आर.के.त्रिवेदी अध्यक्ष, पूर्वी उत्तरप्रदेश, सुदेश जैन संयोजक दिल्ली प्रदेश, प्रदुमन जैन सदस्य दिल्ली प्रदेश, पवन शर्मा सदस्य दिल्ली प्रदेश, पुष्पेंद्र मलिक सदस्य दिल्ली प्रदेश एवं डॉ.इन्दुजैन मौजूद थे।

अमीर जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द ने कार्यकर्ताओं से संगठन और मुस्लिम समुदाय से परे बड़े समाज तक पहुंचने का आह्वान किया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। हैदराबाद में तीन-दिवसीय अखिल भारतीय सदस्य सम्मेलन के दूसरे दिन जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के कैडर सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जमाअत के अमीर (अध्यक्ष) सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने सदस्यों से अपने संगठनात्मक दायरे और मुस्लिम समुदाय से आगे बढ़कर अपनी पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने बड़े समाज तक पहुंचने के लिए ₹RISE₹ नामक शब्द का प्रयोग किया जिसका विस्तार है - R = Reach out (संगठन से परे जुड़ाव बढ़ाना), I = Individual Contribution (व्यक्तिगत पहुंच, सुधार और सेवा पर ध्यान केंद्रित करना), S = Shift in Public Opinion (सार्वजनिक धारणा में सकारात्मक बदलाव लाना) और E = Engagement (उस पहुंच को बढ़ाने के लिए व्यापक मुस्लिम समुदाय को शामिल करना)। सैयद सआदतुल्लाह ने घोषणा की, ₹आइये हम आने वाले वर्ष 2025 को "RISE का वर्ष" बनाएं।₹

जमाअत के अध्यक्ष ने सदस्यों और कार्यकर्ताओं के असीम उत्साह और बलिदान को स्वीकार किया तथा इन विशेषताओं को आंदोलन की अमूल्य संपत्ति बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची सफलता धन या संसाधनों से नहीं बल्कि गुणी और मजबूत पीढ़ियों के पोषण से मापी जाती है। उन्होंने बताया कि एसआईओ और जीआईओ जैसे संगठन इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित नेतृत्व को बढ़ावा देकर इस पीढ़ी-निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सैयद सआदतुल्लाह ने एक सुदृढ़ भविष्य के निर्माण के लिए एक बड़े प्रयास के रूप में युवा और छात्र संगठनों को पोषित करने और समर्थन देने पर तत्काल ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने आंदोलन में महिलाओं के बढ़ते योगदान की सराहना की तथा कहा कि उच्च शिक्षा स्तर और तकनीकी प्रगति के कारण उनकी भूमिका में काफी विस्तार हुआ है।

वर्तमान राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करते हुए जमाअत के अमीर ने एक सक्रिय और रणनीतिक दृष्टिकोण का आग्रह किया तथा इस बात पर बल दिया कि शिकायतें और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अपर्याप्त हैं। उन्होंने क़ुरआन के इस सिद्धांत को उद्धृत किया कि कठिनाई के बाद आसानी आती है, साथ ही उन्होंने श्रोताओं को चुनौतियों में अवसर देखने के लिए प्रोत्साहित किया। सैयद सआदतुल्लाह ने दृढ़ संकल्प पर जोर दिया और सदस्यों से परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनौतियां क्षणिक हैं। उन्होंने जनमत को आकार देने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण और वैध साधनों के प्रयोग के महत्व को दोहराया।

कैडर कन्वेंशन में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के प्रमुख नेताओं द्वारा विचार प्रकट किये गए। कार्यक्रम की शुरुआत मौलाना एजाज असलम द्वारा क़ुरआन पाठ के साथ हुई जिसके बाद जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, तेलंगाना जोन के अमीर (अध्यक्ष) डॉ. खालिद मुबाशिर अल-जफर ने उद्घाटन भाषण दिया। एसआईओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमीज ई.के. ने समाज के पुनर्निर्माण में छात्रों और युवाओं की भूमिका पर बात की, इसके बाद नेशनल फेडरेशन ऑफ़ जीआईओ की अखिल भारतीय अध्यक्ष सामिया रोशन ने छात्राओं के बीच आंदोलन के तेजी से विकास पर बात की। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ने संगठन के भीतर महिलाओं के लिए नई जरूरतों और दिशाओं पर चर्चा की। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष एस. अमीनुल हसन ने वैश्विक परिदृश्य और न्याय के मुद्दे से इसके संबंध पर प्रकाश डाला। साथ ही, जमाअत के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने देश की मौजूदा चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला।

सदस्य सम्मेलन का मुख्य आकर्षण 'इदराक तहरीक शोकेस' नामक विशेष प्रदर्शनी थी, जिसमें देश भर में सफलतापूर्वक चल रहे 100 से अधिक सामुदायिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम प्रदर्शित किए गए। यह जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उद्देश्यों और मिशनों के साथ संरेखित जमाअत और समान विचारधारा वाले संगठनों की महत्वपूर्ण गतिविधियों और योगदान को प्रस्तुत करता है। अखिल भारतीय सदस्य सम्मेलन के दूसरे दिन 15 समानांतर सत्र आयोजित किए गए, जिनमें से प्रत्येक सत्र जमाअत और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए कार्यों के विशिष्ट क्षेत्र पर केंद्रित था, जैसे मीडिया, शैक्षणिक और लेखन प्रयास, विद्वानों के बीच कार्य, पेशेवर पहुंच, व्यापारिक जुड़ाव, चिकित्सा क्षेत्र की पहल, बच्चों के लिए कार्यक्रम, कानूनी मार्गदर्शन और सहायता, युवा आंदोलन, वक्फ मामले, साहित्य, ब्याज मुक्त वित्त और महिलाए।

दिल्ली की सफ़ाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा– मेयर

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली 16 नवंबर दिल्ली के मेयर महेश कुमार ने आज साउथ जोन के वार्ड संख्या 153 (वसंत विहार) का निरीक्षण किया और क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की समीक्षा की।

इस अवसर पर उप महापौर रविन्द्र भारद्वाज, स्थानीय विधायक प्रमिला टोकस, क्षेत्रीय पार्षद हिमानी जैन, उपायुक्त, साउथ ज़ोन बादल कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे ।

इस अवसर पर मेयर ने वसंत विहार के ए ब्लॉक के ढलाव की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। यहां स्थानीय लोगों ने बताया कि इस ढलाव के बाहर फैले कूड़े कचरे से आसपास बदबू फैल रही है। साथ ही ढालव के पास के सार्वजनिक शौचालय से स्थिति और भी खराब हो रही है।

इस समस्या का संज्ञान लेते हुए, महेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द अतिरिक्त गाड़ियों व कार्मिकों को लगाकर ढलाव की सफाई को सुनिश्चित करें।

महेश कुमार ने कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विजान में, मैं और मेरे साथी उप महापौर रविन्द्र के साथ, दिल्ली के हर वार्ड में जाकर वहां की सफाई व्यवस्था का जायजा लेंगे।"

निरीक्षण के दौरान मौजूद उप महापौर रविन्द्र भारद्वाज ने कहा कि हम वसंत विहार वार्ड में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने आए हैं। उन्होने कहा "यह अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को सबसे खूबसूरत शहर बनाने के उनके विजन के अनुरूप है। इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम सफाई व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए जमीनी स्तर पर आज वसंत विहार क्षेत्र में आए हैं।"

इसी क्रम में मेयर ने बसंत गांव की सफाई व्यवस्था का जायज़ा लिया। क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान मेयर ने जाना कि बसंत गांव के पार्क में कचरा कई कई दिनों से फैला हुआ है ।

इस अवसर पर मेयर महेश कुमार ने अधिकारियों को पार्क में पड़े कूड़े कचरा को तत्काल उठा कर इन सभी स्थानों को साफ करने के निर्देश दिए ।

निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया की बसंत गांव की मुख्य सड़क पर आवारा पशुओं का जमावड़ा है। मेयर ने इस संबंध में उपस्थित अधिकारियों को इन आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश दिए।

मेयर ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को साफ सुथरी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मेयर ने कहा की दिल्ली में सफ़ाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे अधिकारियों के साथ सभी वार्ड में सफ़ाई व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए लगातार निरीक्षण करती रहेगी ताकि ज़मीनी स्तर पर सफ़ाई का कार्य हो।

दिल्ली में लगेंगे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-4 के प्रतिबंध! अगले चार महीने तक लोगों को झेलनी होगी परेशानी; अटके सारे काम

दिल्ली में प्रदूषण के कारण GRAP-3 के प्रतिबंध लगने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। अगले चार महीनों तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी की लगभग सभी परियोजनाओं की गति धीमी हो गई है। इस दौरान सड़कों की मरम्मत और खोदाई कार्य पर प्रतिबंध है।

नई दिल्ली। हर साल की तरह इस बार भी प्रदूषण दिल्ली के काम रोकने के लिए तैयार है। ग्रेप तीन के लगने के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की लगभग सभी परियोजनाओं की गति धीमी हो गई है और ग्रेप चार के लगने के बाद काम बिल्कुल ठप होगा। ग्रेप चार के बहुत जल्द लगने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर फरवरी 2025 तक काम इसी तरह प्रभावित रहेगा।

ऐसे में सवाल यही उठता है कि यह सब जानते हुए भी पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं को लेकर उस समय में काम पर अधिक फोकस क्यों नहीं बढ़ता है जब दिल्ली में काम पर किसी तरह की रोक नहीं होती है। सीधी सी बात है कि प्रदूषण के चलते चार माह के दौरान हर साल काम बंद रहने के पिछले सालों की स्थिति से पीडब्ल्यूडी ने कोई सबक क्यों नहीं लिया है।

फ्लाईओवर और अंडरपास की छह बड़ी परियोजनाएं

बहरहाल दिल्ली की बात करें तो इस समय दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने के तहत फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने की छह बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है। जबकि अस्पतालों में बेड बढ़ाने की 15 और चार नए अस्पताल बनाने की परियोजनाएं शामिल हैं। हालांकि अस्पतालों से संबंधित परियोजनाओं को फंड नहीं मिल पाने से पहले से धीमी गति से काम चल रहा है।

फ्लाईओवरों की योजना के लिए फंड की अड़चन नहीं

मगर फ्लाईओवरों की योजना के लिए फंड की अड़चन नहीं है। अगर परियोजनाओं के बीच आ रहे हरे पेड़ों के मुद्दे को अलग कर दें तो और कोई ऐसी अड़चन नहीं है कि जिससे परियोजना की गति धीमी हो सके। मगर अब जो समय आ गया है इसके चलते काम के प्रभावित होने की पूरी संभावना है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब तक प्रदूषण कम नहीं होगा तो काम लगभग ठप रहेगा। इससे परियोजनाओं के पूरी होने में कम से कम चार माह और देरी हो सकती है।

सड़कों की मरम्मत और खोदाई कार्य पर प्रतिबंध

उन्होंने बताया कि अभी परियोजनाओं के काम पर रोक नहीं है, मगर जिस तरह के प्रतिबंध ग्रेप तीन में लगाए गए हैं उनसे काम होना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्रेप तीन में सड़कों की मरम्मत और खोदाई कार्य पर प्रतिबंध है। ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता है जिससे धूल हो, जबकि निर्माण कार्य में 50 से 70 प्रतिशत तक काम किसी न किसी कारण से धूल वाला ही होता है।

सिग्नल फ्री करने के लिए चार बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू

ढांचागत विकास की परियोजनाओं की बात करें तो पिछले 2022 में सड़कों को सिग्नल फ्री करने के लिए चार बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया था। इसके तहत नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाकर लोगों को जाम से राहत देने की तैयारी शुरू की गई थी। इसके तहत 10 अक्टूबर 2022 को अप्सरा बॉर्डर परियोजना का शिलान्यास किया गया है। पंजाबी बाग फ्लाईओवर का 29 सितंबर 2022 को शिलान्यास किया गया। नवंबर 2022 में नंद नगरी में गगन सिनेमा लालबत्ती पर फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू हुआ।

अप्सरा बॉर्डर और पंजाबी बाग का काम लगभग पूरा

इन सभी परियोजनाओं को दो साल के अंदर ही पूरा हो जाना था, अप्सरा बॉर्डर और पंजाबी बाग का काम लगभग पूरा है। मुकरबा चौक व हैदरपुर मेट्रो रोड को जाममुक्त बनाने के लिए तीन अंडरपास का 27 सितंबर 2022 को शिलान्यास किया गया। यह काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। प्रगति मैदान के पास भैरों मार्ग से रिंग रोड पर जाने के लिए अंडरपास को बनाने का काम चल रहा है। यमुना खादर में मयूर विहार फेज-एक के सामने बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर फेज-तीन का काम चल रहा है। यह काम समय से सात साल पीछे है।

ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट टीम ने शनिवार को हरियाणा और उत्तराखंड सरकार के बीएस -4 की डीजल बसों का चालान किया- गोपाल राय

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार दिल्ली को वायु प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज ग्रेप -3 के नियम को सख्ती से लागू करवाने के लिए कश्मीरी गेट आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के औचक निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि आसपास के राज्यों से प्रतिबंध के बाद भी बीएस 4 बसें बस अड्डे पर आ रही है। ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट टीम ने आज हरियाणा और उत्तराखंड सरकार के बीएस -4 की डीज़ल बसों का चालान किया। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण भाजपा की सरकारें बढ़ा रही है और वो प्रतिबंध होने के बावजूद बीएस -4 की डीज़ल बसों को उनके द्वारा दिल्ली भेजा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें जान बूझ कर दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाने के लिए डीज़ल बसें भेज रहे हैं, जो प्रतिबंधित है.

गोपाल राय ने कहा कि वास्तव में दिल्ली में जो प्रदूषण है ,सी एस ई के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के स्रोतों का योगदान 30 प्रतिशत है और शेष एनसीआर के जिलों का योगदान है। दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए समर एक्शन प्लान और विंटर एक्शन प्लान बनाकर कर पुरजोर प्रयास कर रही है लेकिन पड़ोसी भाजपा की सरकार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा रही है। प्रतिबंध होने के बावजूद बीएस -4 की डीज़ल बसों को दिल्ली भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आनंद विहार में उत्तरप्रदेश से डीजल की बसें आ रही है जिससे वहां प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में हरियाणा से , राजस्थान से ,उत्तरप्रदेश से डीजल की बसें आ रही हैं।

बस अड्डे का औचक निरीक्षण के दौरान पर्यावरण मंत्री ने वहां पर बाहर से आनी वाली बसों की जांच किया और जांच में पाया कि कुछ बीएस -4 की बसों का दिल्ली में अभी भी प्रवेश हो रहा है। उन्होंने परिवहन विभाग को इसके लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध को लागू कराने के लिए परिवहन विभाग के 84 टीम और ट्रैफिक पुलिस की 280 टीम लगायी गयी है। गोपाल राय ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है , साथ ही बीएस-3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के दिल्ली रजिस्टर्ड डीजल

मीडियम गुड्स वीकल (एमजीवी) दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। बीएस-3 और इससे नीचे के डीजल एल सी वी मीडियम गुड्स करियर जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। जरूरी सामान और सेवा से जुड़े वाहनों को इसमें छूट है। एनसीआर से आने वाली इंटरस्टेट सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों, सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल बसों को आने की छूट दी गई है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो 20,000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा।

'अभी भी कन्हैया जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे हैं', दिल्ली धर्म संसद में देवकी नंदन ठाकुर का दावा

परिवहन विशेष न्यूज

सनातन धर्म संसद में संतों ने सनातन बोर्ड के गठन और हिंदू धर्म की रक्षा की मांग की। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा अभी भी कन्हैया जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे हैं। संसद में मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की विवादों से मुक्ति हिंदू लड़कियों की शादी हिंदू परिवारों में ही हो धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए आर्थिक मदद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

पूर्वी दिल्ली। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर यमुनापार स्थित न्यू उस्मानपुर के पांचवां पुश्ता में शनिवार को सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। देश के अधिकतर मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। उनमें कार्यरत सरकारी अधिकारियों को धर्म व पूजन विधि का क, ख, ग का ज्ञान नहीं है और न ही वे मंदिरों की देखरेख व रक्षा कर पाने में सक्षम हैं। हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशु की चर्बी की मिलावट होना भी इसी लापरवाही को दर्शाता है। ऐसी घटना दोबारा न हो सके, इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का गठन करना चाहिए। बोर्ड के गठन होने से गुरुकुल परंपरा को जागृत किया जाएगा, गोशालाएं बनाई जाएंगी।

उक्त बातें सनातन न्यास फाउंडेशन के अध्यक्ष व कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने न्यू उस्मानपुर के पांचवें पुश्ते पर शनिवार को आयोजित सनातन धर्म संसद में कहीं। इसका आयोजन सनातन न्यास फाउंडेशन के तत्वाधान में किया गया था। इसमें 13 अखाड़ों से संत पहुंचे थे। पहली धर्म संसद इसी वर्ष 25 फरवरी को दिल्ली व दूसरी धर्म संसद ऋषिकेश में 23 जून को आयोजित की गई थी।

मथुरा में अपने कन्हैया का भव्य मंदिर बनाओ: देवकीनंदन ठाकुर

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की विवादों से मुक्ति भी इस धर्म संसद का विषय था। इस पर बोलते हुए देवकीनंदन ने पंडाल में मौजूद भक्तों से कहा कि अभी भी कन्हैया जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे हैं। यदि आपका जमीर जिंदा है तो फिर मथुरा में अपने कन्हैया का भव्य मंदिर बनाओ। इसके अलावा उन्होंने हिंदू लड़कियों की शादी हिंदू परिवारों में ही हो, ऐसा कानून बनाने की भी मांग की।

एकजुट होकर हिंदुओं की संख्या बढ़ानी है: देवकीनंदन ठाकुर

उन्होंने कहा कि जिनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, उन्हें सनातन बोर्ड के जरिए आर्थिक मदद करके धर्म परिवर्तन को रोकना है। चूंकि घटता हुआ हिंदू, देश के लिए खतरा है, इसलिए एकजुट होकर हिंदुओं की संख्या बढ़ानी है। साथ ही कहा कि जो लोग हलाल सर्टिफिकेट लेकर सामान बेच रहे हैं, हिंदू समाज को उसका बहिष्कार करना है। देवकीनंदन ने 'अभी नहीं तो कभी नहीं' नारे के साथ-साथ 'बहुत सह लिया अब नहीं सहेंगे, हिंदू हक अब लेकर रहेंगे' का नारा भी दिया।

इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी महाराज, महामंडलेश्वर नवल किशोर महाराज, अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य लोकेश मुनि, कौशिक महाराज व अन्य संत मौजूद हैं।

एक हो गए तो कोई अलग नहीं कर सकता: शंकराचार्य सदानंद

सनातन धर्म संसद में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे द्वारका शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि जब तक सबसे पहले सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा नहीं होगी, तब तक बोर्ड के गठन की सफलता नहीं मिलेगी। यदि हम एक हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है और कोई हमें आंख भी नहीं दिखा सकता है। गोमाता की रक्षा करनी चाहिए, शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, यज्ञशाला, पाठशाला, गुरुकुल की परंपरा फिर शुरू होनी चाहिए। हम सनातनियों को प्राचीन वैदिक परंपरा को संरक्षित करना होगा। जिस प्रकार धर्मी में धर्म होना चाहिए, जल में जलत्व होना चाहिए, उसी प्रकार हिंदू में हिंदुत्व होना चाहिए, तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी।

विभिन्न संतों के बयान

जब लोग संतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो तत्काल ही सनातन बोर्ड का गठन होगा। वर्तमान में हमारे संस्कारों और विचारों की सरकार है। ऐसे में जल्द ही बोर्ड का गठन होने की उम्मीद है। - राजू दास महाराज, हनुमानगढ़ी महंत

राष्ट्र बचाने की जिम्मेदारी अब लोगों की है। हिंदुओं को जागना होगा। सनातनियों के लिए अपने सदस्यों की, स्वयं की, परिवार की, राष्ट्र की रक्षा प्राथमिकता है। शास्त्रों और शस्त्रों का साथ बनाकर चलना होगा। - पंडित प्रदीप मिश्रा

सनातनियों को दूसरे समुदायों के बजाय विपक्षी नेताओं से अधिक खतरा है। वैसे तो न हम किसी को काटते हैं और न ही डांटते हैं, लेकिन हमें बांटने वालों और काटने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। - गोविंद देव गिरी जी महाराज, कोषाध्यक्ष, श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट, अयोध्या

वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड है, जिसकी भारत की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। यह बोर्ड पूरा असंवैधानिक है। सनातन बोर्ड होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड का नामोनिशान नहीं होगा। सनातन बोर्ड गठित होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। यदि समय से होगा तो बढ़िया है, अन्यथा हमें साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनानी होगी। - साध्वी सरस्वती

गाजियाबाद में सीएम योगी का रोड शो शुरू, आसपास लोगों का लगा जमावड़ा

लोकसभा चुनाव के दौरान जिस खुले वाहन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गाजियाबाद शहर में रोड शो किया था उसी वाहन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में प्रदेश सरकार के चार मंत्री जिले के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। इस दौरान एक लाख से अधिक लोगों के मौजूद रहने की संभावना है और 25 से अधिक ब्लॉक बनाए गए हैं।

ग्रेटर नोएडा। गाजियाबाद। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद में शनिवार शाम को रोड शो शुरू हो गया। उनका रोड शो चाणक्य चौक से शुरू हुआ है। वह भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। 20 नवंबर को गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है।

सीएम योगी उसी वाहन से रोड शो कर रहे हैं, जिस वाहन से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गाजियाबाद शहर में रोड शो किया था। सीएम योगी खुले वाहन में खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद है। रोड शो में प्रवेश करने वाले लोगों को हाथ में भाजपा का बैंड पहनना पड़ रहा है।

10 क्विंटल फूलों की वर्षा

चाणक्य चौक से प्रताप विहार स्थित डीएववी चौक के बीच 1,200 मीटर लंबे इस रोड शो में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए हर वर्ग के लोग सौ से अधिक स्थानों पर उपस्थित हैं। रोड शो के दौरान आसपास मौजूद लोग पुष्पवर्षा कर रहे हैं। रोड शो में कुल 10 क्विंटल से अधिक फूलों की वर्षा की जाएगी। लगभग एक लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति रोड शो के कार्यक्रम में रहने की संभावना है।

गुरुग्राम में सात कालोनियों पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने 25 एकड़ जमीन को किया कब्जा मुक्त

गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार एनफोर्समेंट (डीटीपीई) की तरफ से साढ़राना तथा गढ़ी हरसरू गांव में सात अवैध कालोनियों में तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। यह कालोनियां करीब 25 एकड़ में काटी जा रही थीं।

विभाग की तरफ से पहले कारण बताओ नोटिस और रेस्टोरेशन के आदेश जारी किए गए और उसके बाद बुधवार और गुरुवार को लगातार दो दिन तोड़फोड़ की गई। इस दौरान सेक्टर 10ए से पुलिस बल मौजूद रहा। डीटीपीई ने बताया कि साढ़राना गांव में करीब नौ एकड़ में तीन नई अवैध कालोनियां काटी जा रही थीं।

पूरी ब्लैक टॉप सड़क नेटवर्क को किया गया ध्वस्त

इसमें एनफोर्समेंट टीम ने तोड़फोड़ कारवाई करते हुए करीब 400 मीटर की चारदीवारी, 75 डीपीसी को ध्वस्त कर दिया गया और पूरे सड़क नेटवर्क को उखाड़ दिया। इसके बाद टीम गढ़ी हरसरू गांव में पहुंची।

यहां पर 16 एकड़ में अवैध रूप से चार कालोनी काटी जा रही थीं। टीम ने तोड़फोड़ कारवाई करते हुए 58 डीपीसी, 100 मीटर प्रीकास्ट चारदीवारी, एक डीलर कार्यालय, सात अन्य चारदीवारी और पूरी ब्लैक टॉप सड़क नेटवर्क को ध्वस्त किया गया।

मेहनत की कमाई का अवैध कालोनियों में निवेश न करने की सलाह

डीटीपीई मनीष यादव ने तोड़फोड़ के दौरान उपस्थित लोगों से अपील की है कि वे अपनी मेहनत की कमाई इन अवैध कालोनियों में निवेश न करें। किसी भी भूमि/प्लॉट की खरीद से पहले डीटीपी कार्यालय से जानकारी लें। कारवाई के दौरान डीटीपीई मनीष यादव के अलावा एटीपी अनीश ग्रोवर बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जूनियर इंजीनियर नवीन, अमित, हर्षित, परमिल समेत डीटीपीई कार्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।

गुरुग्राम में एक दर्जन फार्म हाउस जमींदोज

Bulldozer action in Raisina Hills: हरियाणा में बनी नई सरकार का असर दिखने लगा है। महीनों की चुप्पी के बाद परिषद ने कार्रवाई की है। पहली बार 22 एकड़ में विकसित 12 अवैध निर्माण को गिराया गया।

अरावली पहाड़ी में रायसीना से लगती पहाड़ी में अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। तीन घंटे की चली इस तोड़फोड़ में लगभग 12 अवैध निर्माण की चारदीवारी, पक्के मकान और स्विमिंग पूल को ढ़हाया गया।

टीबी मरीजों को अब मिलेगी 1000 की आर्थिक मदद, केंद्र का 2025 तक टीबी मुक्त का लक्ष्य

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम शहर में टीबी के बैक्टीरिया का फेफड़ों पर अटैक जारी है। पिछले साल की तुलना में इस साल 1161 मामलों में इजाफा देखा गया। नवंबर महीने में अब तक खोजे गए 225 टीबी रोगियों को सरकारी आर्थिक सहायता के रूप में 500 रुपये की जगह पर अब 1000 रुपये मिलेंगे। बता दें यह पैसा रोगियों की डाइट के लिए दिया जाता है।

गुरुग्राम। जिले में टीबी के बैक्टीरिया का फेफड़ों पर प्रहार जारी है। इस बात की तस्दीक स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े करते हैं। पिछले साल के मुताबिक इस साल 1161 मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल 7090 रोगी मिले थे, जबकि इस बार 11 महीनों में 8251 टीबी रोगियों की पहचान हो चुकी है।

इसमें नवंबर महीने में अब तक खोजे गए 225 टीबी रोगियों को अनुदान के रूप में 500 रुपये की जगह 1000 रुपये दिए जाएंगे। क्योंकि प्रदेश सरकार ने रोगियों के डाइट अनुदान को दोगुना कर दिया है। केंद्र सरकार का देश को 2025 तक टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य है। क्षय विभाग की ओर से स्क्रीनिंग व जागरूकता अभियान जारी है।

वर्ष 2023 में जिले में 70673 लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी। इसमें से 35994 लोग जांच के लिए आगे आए थे। इस वर्ष अब तक 66247 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 66303 लोगों ने जांच कराई है। इसमें 8251 लोगों में टीबी रोगी की पुष्टि हुई है।

जिले में मरीजों में 55 प्रतिशत फेफड़े की और 45 एक्स्ट्रा पल्मोनरी शामिल है। विशेषज्ञों बताते हैं कि टीबी का बैक्टीरिया सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि रीढ़ व हड्डी को भी खोखला रहा है। इतना ही नहीं महिलाओं का गर्भाशय भी इससे संक्रमित हो रहा है। स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ने के साथ-साथ रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बच्चों से लेकर वृद्ध टीबी के संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं।

यह होता है रोगी का कोर्स

मरीज को पहली स्टेज में छह से आठ महीने तक रोजाना दवा लेनी होती है। कोई मरीज बीच में दवा छोड़ देता है तो उसे दोबारा मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंट टीबी (एमडीआर) होगी। उस मरीज को 24 से 27 माह तक हर रोज दवा लेनी होगी।

एमडीआर से ग्रस्त मरीज बीच में दवा छोड़ देता है तो उसकी बीमारी जानलेवा बनकर वापस लौटती है, जिसे एक्सट्रीम ड्रग रिजीसटेंट (एक्सडीआर) टीबी कहते हैं। एक्सडीआर मरीज को 27 से 30 माह तक दवा लेनी होगी।

साल	मरीजों की संख्या
2019	7108
2020	5736
2021	6294
2022	6851
2023	7090
2024	8251 (अब तक)

घर-घर जाकर हो रही खोज

स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी रोगियों की खोज के लिए एक नवंबर से डोर-टू-डोर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 1050 आशा वर्कर की ड्यूटी लगाई गई है। जो अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में जाकर स्क्रीनिंग कर रही है।

एक नजर में

- 441 हैं एक वर्ष 14 वर्ष के रोगियों की संख्या
- 3572 मिली हैं टीबी से ग्रसित महिलाएं
- 4676 है जिले में टीबी से पीड़ित पुरुषों की संख्या
- 4000 के करीब रोगियों को इस वर्ष लिया गया है गोद
- 6089 टीबी रोगियों को दिया जा रहा है अनुदान
- 03 प्रतिशत टीबी रोगियों की होती है हर साल मृत्यु
- 06 हैं ट्रीटमेंट यूनिट
- 22 हैं जिले में माइक्रो स्कोपिक सेंटर
- 15 केंद्रों पर होती है बलगम की जांच

जीवन के अंतिम पड़ाव में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के सहयोग से देख पढ़ सुन रहे हैं कि दुनियाँ में असंख्य माता पिता वह सीनियर सिटीजन बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो अपनी संतान की दुत्कार सह रहे होंगे। आज मॉडर्न सोसाइटी का तर्क देकर माता पिता, बुजुर्गों से दुर्व्यवहार किया जाता है।आज थोड़ी-थोड़ी बात पर माता-पिता बुजुर्गों को कहा जाता है कि चुपचाप बैठो, तुमको क्या समझता है, तुम सठिया गए हो।हालांकि भारत एक आध्यात्मिक माता-पिता का संबंध, बुजुर्गों की सेवा करने के विचारों महान मानवों का देश है। परंतु आज वह केवल उदाहरण बनकर रह गए हैं।प्रैक्टिकली अगर माता-पिता बुजुर्गों के जीवन में झांक कर देखा जाए तो आज की तारीख में उन्हें दुत्कार ही मिलती रहती है। मैंने अपनी गोंदिया राइस सिटी में इसे रिसर्च के तौर पर माता-पिता द्वारा 1 साल के बच्चों की परवरिश पर पूरा एक महीना ध्यान रखा तो देखा वह अपने बच्चों को, माता पिता अपने पलकों पर बैठा कर प्यार करते हुए ए ग्रेड का पालन पोषण कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एक परिवार को देखा जिसमें जिसके दोनों बच्चे मुंबई पुणे और विदेश में रह रहे थे और मां लाचार होकर किचन में तो पिता छोटी सी दुकान पर अपनी बुजुर्ग दौर के दिन मेहनत करके काट रहा था।तीसरी जगह देखा तो बच्चे अपने माता-पिता को दुत्कार कर रौब से बात कर रहे थे कि मानो वह उसके माता पिता नहीं उसके घर के नौकर है। यह तीनों ग्राउंड रिपोर्टिंग किस्से देखकर मैं दंग रह गया। यानें बच्चों को हम कितना लाड से पालते पोछते पढ़ाते और लाखों के पैकेज की नौकरी योग्य बनाते हैं कई बार तो उन्हें ढूंढ कर नौकरी भी दिलाते हैं, तो दूसरी ओर वह जाब करने बड़ी सिटियों या विदेश जाकर बस जाते हैं और माता-पिता बुजुर्गों को भूल जाते हैं। अगर बच्चे माता-पिता के साथ भी रहते हैं तो माता पिता बुजुर्गों को नौकर बना कर रखते हैं, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए शर्म की बात है, यह देखकर मुझसे रहा नहीं गया और उस रिसर्च के आधार पर इस आर्टिकल में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध जानकारी का सहयोग भी लिया हूं। माता-पिता बुजुर्गों के सम्मान को रखना, वर्तमान मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस (अमेंडेड) एक्ट 2019 नाकाफी व अपर्याप्त है। अब वह समय आ गया है कि माता-पिता बुजुर्गों के साथ दुर्व्यहर, बुरा व्यवहार अपमान व प्रताड़ित करने वालों पर एस्ट्रासिटी के समकक्ष कानून बनाने की जरूरत आन पड़ी है, जो संभवतः25 नवंबर 2024 से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में लाने की ज़रूरत है।

साथियों बात अगर हम सूचीगत जातियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 2019 के समक्ष माता-पिता बुजुर्गों के सम्मान के लिए कानून बनाने की करें तो जिस तरह सामाजिक सौहार्दपूर्णता समानता को कायम रखने के लिए एस्ट्रासिटी (अमेंडेड)कानून 2019 बनाया गया है जिसका डर हमेशा उपद्रवी लोगों में बना रहता है या फिर कभी नए फौजदारी अधिनियम 2023 में क्राइम को रोकने अनेक धाराओं का डर लोगों में बना हुआ है उसी तर्ज पर मेरा सुझाव है कि आने वाले 17 वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में माता-पिता बुजुर्गों के साथ होने वाली क्रूरता दुष्टपरिणाम दुर्व्यवहार अपमान व दुत्कार पर लगाम लगाने के लिए माता-पिता वह वरिष्ठ नागरिक (अत्याचार अपमान दुर्व्यवहार व्यवहार व दुराचार) विधेयक 2024 बनाकर पेश किया जाए जिसे सभी पार्टियों एक मत होकर 544/0 मतदान से पारित करेंगी ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

साथियों बात अगर हम माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2019 की करें तो, प्रावधान-धारा 2 डी के तहत इन्हें मिलेगा फायदा, जन्मदाता माता पिता, दत्तक संतान ग्रहण करने वाले, सौतेले माता और पिता धारा 2(जी) उनके लिए जिनके बच्चे नहीं- अधिनियम की ये धारा उनके लिए हैं, ऐसे में उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी वे संबंधी उठाएंगे जो

उनकी संपत्ति के हकदार हैं।धारा 5 के ये हैं लाभ, वे वरिष्ठ नागरिक जिनकी देखरेख उनके बच्चे या संबंधी नहीं कर रहे है वे एसडीएम कोर्ट (ट्रिब्यूनल) में शिकायत करसकते हैं।-प्रार्थना पत्र चाहे स्वयं दें या फिर किसी एनजीओ के माध्यम से दे सकते हैं। ऐसे मामलों का ट्रिब्यूनल खुद भी संज्ञान ले सकता है।-बच्चों अथवा संबंधियों को नोटिस मिल जाने के बाद 90 दिन के अंदर फैसला हो जाता है। अपवाद की स्थिति में 30 दिन समय बढ़ाया जा सकता है।-माता-पिता चाहें तो अपने सभी पुत्र-पुत्रियों अथवा किसी एक के खिलाफ भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।अंतरिम गुजारा भत्ता की राशि ट्रिब्यूनल दस हजार रुपये तक तय कर सकता है। न देने पर जेल भी हो सकती है।ट्रिब्यूनल प्रार्थना पत्र को समझौते के लिए नामित अधिकारी के पास भी भेज सकते हैं।देखभाल नहीं की तो नहीं मिलेगी संपत्तिधारा-14- सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का वाद न्यायालय में लंबित है तो वापस लेकर ट्रिब्यूनल में लगाया जा सकता है।धारा-19- राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कम से कम एक ओल्ड एज बनाएगी। इसमे 150 लोग रखे जासकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के रहने खाने, चिकित्सा, मनोरंजन कीजिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।धारा-20 - जिले के सरकारीचिकित्सालयों में बेड आरक्षित करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होगी।धारा-23मातापिता ने अपनी संपत्ति बच्चों को दे दी है और बच्चे उनकी सेवा नहीं कर रहे तो संपत्ति पुनः माता पिता के नाम पर आ जाएगी।सुरक्षा के लिए ध्यान रखेंप्रदेश सरकार के निर्देश पर पुलिस ने बुजुर्गों के लिए पॉकेट गाइड जारी की गई है। इसमें बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए कई दिशा निर्देश हैं।-घर में नए कर्मचारी की नियुक्ति से पहले पुलिस वेरीफिकेशन कराएं -घर की कुछ अतिरिक्त चाबियां गुप्त जगह पर रखें।

साथियों बात अगर हम प्रस्तावित कानून में माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक (अत्याचार अपमान दुर्व्यवहार निवारण) विधायक 2024 की जरूरत की करें तो, हमारा देश महान संतानों की भूमि है, यहां बच्चों से अपने बुजुर्ग माता-पिता की उचित देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन पीड़ादायक है कि नैतिक मूल्यों में इस कदर गिरावट आ गई है कि अपना सुख-चैन जिन बच्चों के लिए माता-पिता त्याग कर जीवन खत्म कर देते हैं, वही बच्चे उन्हें बुढ़ापे में दो जून की रोटी और मोहब्बत के लिए तरसा रहे हैं।आजकल कई मामलों में बच्चे अपने माता-पिता से संपत्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं।जो न सिर्फ दुखद है, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों में निरंतर आ रही गिरावट का प्रतीक भी है।हमारे सामाजिक मूल्यों में तेजी से आ रहे बदलाव की वजह से आज बुजुर्गों को अपनी ही संपत्ति में सुरक्षित रहने और संतानों की प्रताड़ना से बचने के लिये उन्हें अपने स्व अर्जित घर से बेदखल करने के लिए अदालतों की शरण में आना पड़ रहा है, इस तरह की उद्दंड संतानों को माता पिता के घर से बेदखल करने के आदेश भी अदालत दे रही हैं लेकिन यह सिलसिला बदस्तूर जारी हैसामाजिक मूल्यों में आ रहे ह्रास का ही नतीजा है कि संपत्ति के लालच में मौजूदा दौर में बेटा-बहू और बेटी द्वारा अपने माता-पिता को बेआबरू करने की घटनाएं और इससे मजबूर होकर बुजुर्गों द्वारा कानूनी रास्ता अपनाने के मामले बढ़ रहे हैं।परिवारों में बुजुर्ग माता पिता और दूसरे वृद्ध सदस्यों को बोझ समझा जाने लगा है. कई बार तो उन्हें उनके ही स्वअर्जित घर से बेदखल करके दर बदर की ठोकरें खाने के लिये छोड़ दिया जा रहा है या फिर सुशिक्षित बेटे बहू उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हैं। हमारा देश महान संतान श्रवण कुमार की भूमि है, यहां बच्चों से अपने बुजुर्ग माता-पिता की उचित देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन पीड़ादायक है कि नैतिक मूल्यों में इस कदर गिरावट आ गई है कि अपना सुख-चैन जिन बच्चों के लिए माता-पिता त्याग कर जीवन खत्म कर देते हैं, वही बच्चे उन्हें बुढ़ापे में दो जून की रोटी और मोहब्बत के लिए तरसा रहे हैं। आजकल कई मामलों में बच्चे अपने माता-पिता से संपत्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं. जो न सिर्फ दुखद है, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों में निरंतर आ रही गिरावट का प्रतीक भी है।

साथियों बात अगर हम माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण (संशोधित) अधिनियम 2019 को बनाने की जरूरत की करें तो, अपने ही देश, समाज और घर परिवार में बेगाने होते जा रहे बुजुर्गों की स्थिति पर उच्चतम न्यायालय ने भी चिंता व्यक्त की है. शीर्ष अदालत ने दिसंबर, 2018 में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि बुजुर्गों के हितों की रक्षा के लिए 2007 में बनाये गये माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कानून के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए।शीर्ष अदालत ने डॉ अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्वीकार किया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा था कि हम कई अधिकारों से सहमत हैं लेकिन फिलहाल हमारा सरोकार तीन महत्वपूर्ण संवैधानिक मौलिक अधिकारों से है।संपन्नता की सीढ़ियों में आगे बढ़ रहे पुत्र पुत्रियों और बहू तथा दामादों के दुर्व्यवहार के कारण घर की चारदीवारी के भीतर रहने वाले विवाद अदालतों में पहुंचने लगे हैं।अपनी संतानों के आचरण से आहत बुजुर्ग माता पिता अब उन्हें अपने मकान से बेदखल कराने जैसे कठोर कदम उठाने लगे हैं।स्थिति की गंभीरता और बुजुर्गों को इस दयनीय स्थिति से संरक्षण प्रदान करने के इरादे से 2007 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कानून बनाया बुजुर्गों के हितों की रक्षा के मामले में न्यायपालिका ने भी सख्त रुख अपनाया।यह कानून बनने के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, और पंजाब सहित कई राज्यों में संतानों के दुर्व्यवहार से पीड़ित बुजुर्ग माता-पिता अथवा एकाकी जीवन बिताने वाले बुजुर्गों ने अदालतों और न्यायाधिकरणों की शरण ली। अदालतों ने ऐसे मामलों में सारे तथ्यों की विवेचना के बाद ऐसी उद्दंड और गैर जिम्मेदार संतानों, उनकी पत्नियों तथा ऐसे ही दूसरे परिजनों को घरों से बेदखल करने का आदेश भी दे दिया गया है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि जीवन के अंतिम पड़ाव में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहारमाता-पिता व बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहारअपमान व प्रताड़ित करने वालों पर एस्ट्रोसिटी के समकक्ष कानून बनाने की जरूरत।चुपचाप बैठो, तुमको क्या समझता है, तुम सठिया गए हो माता पिता सीनियरसिटीजन (अत्याचार अपमान व दुर्व्यवहार निवारण) विधेयक 2024 बनाने की जरूरत माता-पिता व बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा, गरिमा भरे जीवन को सुरक्षित करने, वर्तमान कानून व नियम अपर्याप्त हैं, इसको रेखांकित करने करना जरूरी है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स सभी ओलंपिक मेडल विनर्स को गिफ्ट की विंडसर ई.वी, लिस्ट में नीरज चोपड़ा और मनु भाकर भी शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ओलम्पिक 2024 में भारतीय दल ने एक सम्मानजनक उपलब्धि हासिल करने में अदम्य साहस दिखाया और भविष्य के महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। उनकी इस कड़ी मेहनत और सदैव उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के प्रयासों का सम्मान करने के लिए, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने इन स्पोर्ट स्टार्स को नई एमजी विंडसर, जो भारत की पहली इंटेलिजेंट सीयूवी है, और जिसने भारतीय पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार बाजार में एक बड़ी हलचल मचाई है, देकर सम्मानित किया है।

JSW MG की खास पहल

भारत के ओलम्पिक पदक विजेताओं ने भाला फेंक, पिस्टल और राइफल शूटिंग, कुश्ती और हॉकी जैसे विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लिया और पदक जीते। इन प्रतिष्ठित ओलम्पियनों को चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों ने उन्हें उनकी नई एमजी विंडसर की चाबियां सौंपी। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के डायरेक्टर पार्थ जिंदल, जेएसडब्लयू एमजी मोटर इंडिया के सीईओ एमेरिट्स राजीव छाबा, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बीजू बालेंदरन, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के चीफ ग्रोथ ऑफिसर गौरव गुप्ता, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर सतिंदर सिंह बाजवा और देशभर से आए एमजी के डीलर पार्टनर शामिल थे।

इन लोगों को मिली एमजी विंडसर ईवी

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने ओलंपिक मेडल विनर्स को सम्मानित किया। जिसमें से सबसे पहला नाम नीरज चोपड़ा आ आता है, जिन्होंने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही शूटिंग में मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता था। रेसलिंग से अमन सहरावत मिली। विनेश फोगाट को भी इससे सम्मानित किया गया है, जो मेडल जीतने से चूक गईं। पैरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम से जुड़े 19 खिलाड़ियों को भी एमजी विंडसर ईवी गिफ्ट के रूप में दी गई है। इंडियन हॉकी टीम में ब्रोन्ज मेडल जीता था।

एमजी विंडसर के फीचर्स

भारत की पहली इंटेलिजेंट सीयूवी, एमजी विंडसर को अपने लॉन्च के बाद से ही ग्राहकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। बुकिंग शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही इसने 15,000 से ज्यादा एडवांस बुकिंग हासिल की और अक्टूबर महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार बन गई है। एमजी विंडसर सेडान के कम्फर्ट और एक एसयूवी के आकार दोनों का मिश्रण है, जो ग्राहकों को शानदार बिजनेस क्लास अनुभव प्रदान करता है। इसे फ्यूचरिस्टिक एयरोडायनामिक डिजाइन, विशाल और शानदार इंटीरियर, भरोसेमंद सुरक्षा, स्मार्ट कनेक्टिविटी, ड्राइविंग कम्फर्ट और कई हाई-टेक फीचर्स के साथ पेश किया गया है।

मारुति सुज़ुकी ई विटारा ग्लोबल लेवल हो चुकी है पेश, जानिए एक्सटीरियर और इंटीरियर की पूरी जानकारी

परिवहन विशेष न्यूज

मारुति सुजुकी की पहले इलेक्ट्रिक कार Maruti Suzuki e Vitara ग्लोबल लेवल पर पेश हो चुकी है। मारुति सुजुकी ई-विटारा को भारतीय बाजार में साल 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल 360-डिग्री कैमरा ADAS सूट ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। आइए जानते हैं कि यह कितना खास होने वाली है।

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी ने अपने पहले ऑल-इलेक्ट्रिक कार e Vitara को इटली में पेश किया है। ग्लोबल लेवल यह कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार है, जिसा साल 2025 में भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसे सबसे पहले ऑटो एक्सपो 2023 में प्री-प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट eVX के रूप में पेश किया गया था। साथ ही एक साल बाद भारत मोबिलिटी एक्सपो में भी दिखाया गया था। आइए जानते हैं कि Maruti Suzuki e Vitara को किन फीचर्स से लैस किया गया है।

Maruti Suzuki e Vitara: एक्सटीरियर

इसके कॉन्सेप्ट मॉडल में पॉप-आउट डोर हैंडल देखने के लिए मिले थे और इसका डिजाइन भी काफी फ्यूचरिस्टिक था। वहीं, ई विटारा ने कंपनी की भविष्य में आने वाली मारुति की कारों से डिजाइन के मामले में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। इसके चारों तरफ मोटी क्लैडिंग, चंकी व्हील आर्च और एक मोटे रियर बम्पर के साथ फ्रंट फेशिया को काफी शानदार दिया गया है।

इसके आगे की तरफ हेडलैम्प में क्लस्टर के अंदर Y-आकार के LED DRLs, फ्रंट पार्किंग सेंसर, कैमरा दिया गया है। इसमें 18 इंच और 19 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं।

इसके सामने की तरफ चार्जिंग पोर्ट को दिया गया है, जो व्हील आर्च पर फैला हुआ है। इसके आगे वाले दरवाजे के हैंडल पुल-टाइप हैं और पीछे के दरवाजे के हैंडल C-पिलर में रखे गए हैं

ई-विटारा के पीछे की तरफ की बात करें तो रूफ स्पॉइलर और साइड काउल के साथ एक फ्लोटिंग रूफलाइन इफ़ेक्ट दिया गया है। इसमें दिए गए रियर प्रोफाइल का सबसे बेहतरीन डिजाइन एलिमेंट कनेक्टेड टेललैंप्स हैं।

Maruti Suzuki e Vitara: इंटीरियर और फीचर्स

इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी के डैशबोर्ड को बाकी मारुति की गाड़ियों से काफी अलग दिया गया है। इसमें दी गई स्क्रीन हाउसिंग में एम्बेडेड हैं, जिसके नीचे की तरफ वर्टिकल एसी वेंट हैं। इसे डुअल-टोन ब्लैक और टैन ब्राउन थीम दिया गया है।

मारुति सुजुकी की तरफ से इसके किसी भी तरह के फीचर्स की लिस्ट को शेयर नहीं किया गया है, लेकिन इसमें नया टू-स्पीक स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, ADAS सूट, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और भी बहुत कुछ दिया गया है।

Maruti Suzuki e Vitara: पावरट्रेन

मारुति सुजुकी ई-विटारा नए HEARTECT-e प्लैटफ़ॉर्म पर आधारित है। यह दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आएगी, जो 49 kWh और 61 kWh यूनिट होंगे। पहले इसके केवल 2WD कॉनफ़िगरेशन को ही लेकर आया जाएगा, बाद में दो ड्राइवट्रेन मिलेंगे। जिसके बाद यह 2WD और 4WD के साथ सभी के लिए उपलब्ध होगी। इसमें ALLGRIP-e 4WD सिस्टम भी देखने के लिए मिलेगा।

Maruti Suzuki e Vitara: कीमत

भारत में मारुति सुजुकी ई-विटारा को साल 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमतों की बात करें तो मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार की कीमत 20 लाख से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

भारतीय बाजार में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा ईवी (साल 2025 में लॉन्च), e Tata Curvv EV, MG ZS EV और BYD Atto 3 से देखने के लिए मिलेगा। वहीं, नवंबर 2024 में महिंद्रा की लॉन्च होने जा रही दो इलेक्ट्रिक कार XEV 9e और BE 6e के साथ भी होगा।

स्कोडा वॉक्सवैगन की कुशाक, टाइगन, स्लाविया, वर्टस में आई खराबी, 52 गाड़ियों को किया रिकॉल

परिवहन विशेष न्यूज

Skoda-Volkswagen की चार मॉडल को रिकॉल किया गया है। इन मॉडलों में डा कुशाक और स्लाविया और वोक्सवैगन टाइगुन और वर्टस शामिल है। इन गाड़ियों में वेल्डिंग की समस्या देखने के लिए मिली है। जिसकी वजह से इनके ट्रैक कंट्रोल आर्म में खराबी आ सकती है। इस खराबी की वजह से ड्राइवर अपना कंट्रोल गाड़ी से खो सकता है। इन गाड़ियों की संख्या 52 है।

नईदिल्ली। SIAM की रिपोर्ट के मुताबिक, स्कोडा-वोक्सवैगन की चार गाड़ियों के लिए रिकॉल जारी किया गया है। रिकॉल हुई मॉडल स्कोडा कुशाक और स्लाविया और वोक्सवैगन टाइगुन और वर्टस है। रिकॉल हुई गाड़ियों की संख्या 52 है। इन गाड़ियों को 29 नवंबर 2023 से लेकर 20 जनवरी 2024 के बीच में बनाया गया था। आइए जानते हैं कि इन गाड़ियों को क्यों रिकॉल किया गया है।

Skoda-Volkswagen Recalls: ये है समस्या

SIAM की रिपोर्ट के मुताबिक, इन चारों मॉडलों में वेल्डिंग समस्या की समस्या देखने के लिए मिली है। इसकी वजह से इनके ट्रैक कंट्रोल आर्म में समस्या देखने के लिए मिल सकती है। इसके फेल होने की वजह से ड्राइविंग के दौरान लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइवर अचानक कार पर से कंट्रोल खो सकते हैं। जिसकी वजह से वह हादसे का शिकार हो सकते हैं। SIAM द्वारा प्रदान की गई रिकॉल जानकारी भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार है। यह आम जनता और अन्य हितधारकों के लिए सुलभ है।

रिकॉल के तहत प्रभावित वाहन

- सभी चार मॉडल, कुशाक, स्लाविया, टाइगुन और वर्टस, पुणे के चाकन में बनाए जाते हैं। स्कोडा के मामले में, कुशाक और स्लाविया की 14 गाड़ियों में वेल्डिंग समस्या को लेकर चिन्हित किया गया है। वोक्सवैगन के मामले में, टाइगुन और वर्टस की 38 गाड़ियों को रिकॉल के लिए चिन्हित किया गया है, जो कुल मिलाकर 52 गाड़ियां हो जाती है। गाड़ियों के रिकॉल होने की समस्या कम है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों की मालिकों को व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाएगा।
- जैसा कि अधिकांश रिकॉल मामलों में देखने के लिए मिलता है कि पुर्जों की मरम्मत या बदलने की प्रक्रिया को फ्री में किया जाता है। इसे ठीक करने कितना समय लगेगा, इस बारे में पूरी जानकारी कंपनी के डोमेन पर नहीं जारी की गई है। कार में बेल्डिंग की समस्या हादसे का कारण बन सकता है। ग्लोबल NCAP द्वारा रेट की गई ये भारत की सबसे सुरक्षित कारों में से से एक है।
- इन चारों मॉडल में से कुशाक को हाल ही में भारत की सड़कों को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इसे भारत में साल
- 2021 में लॉन्च किया गया था, अब कंपनी इसके फेसलिफ्ट को लाने की तैयारी कर रही है। इसमें कुछ कॉस्मेटिक टच-अप और ADAS और 360° कैमरा जैसे नए फीचर देखने के लिए मिल सकते हैं।

ओईएम ने पीएम ई-ड्राइव के तहत ई-ट्रक सब्सिडी के प्रभावी उपयोग के लिए घटक प्रोत्साहन का दिया प्रस्ताव

परिवहन विशेष न्यूज

भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक परामर्श बैठक के दौरान टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड सहित भारतीय ट्रक निर्माताओं ने इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए 500 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए घटक-स्तरीय प्रोत्साहन और दीर्घकालिक परिसंपत्ति उपयोग की वकालत की।

मूल उपकरण निर्माताओं यानी के नेताओं ने सरकार से उद्योग को सहायता प्रदान करने के साधन के रूप में विशेष रूप से उच्च प्रभाव वाले ग्राहक-संचालित क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्ति उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक परामर्श बैठक के दौरान जिसमें नीति आयोग, एसआईएएम और सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ओईएम के प्रतिनिधियों ने वाहन-स्तरीय प्रोत्साहनों के अलावा घटक-स्तरीय प्रोत्साहनों पर विचार करने का भी सुझाव दिया।

इसके अलावा वे सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हुए कि ट्रक विद्युतीकरण के शुरुआती चरण में स्थापित मार्गों और पूर्वानुमानित उपयोग पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अशोक लेलैंड में विनियामक मामलों और उत्पाद समरूपता के प्रमुख मुथुकुमार एन ने बड़े ट्रकों के लिए परिचालन की कुल लागत में कमी लाने के लिए ई-कॉमर्स जैसे उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों को लक्षित करने के महत्व पर जोर दिया, जो वर्तमान में पारंपरिक ईंधन पर चल रहे हैं।

वर्तमान में टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक ट्रकों के सबसे व्यापक चयन के साथ बाजार में अग्रणी हैं।

टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहन कारोबार के लिए रणनीति प्रमुख प्रसाद फड़के ने सब्सिडी निधि की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए स्थायी परिसंपत्ति उपयोग की पहचान करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

इसके अलावा महिंद्रा ट्रक और बस डिवीजन में होमोलोगेशन के प्रमुख वीजी कुलकर्णी सहित विशेषज्ञों ने महिंद्रा के ई-ट्रकों के बारे में जानकारी दी और वाहन-स्तरीय प्रोत्साहनों के साथ-साथ घटक-स्तरीय प्रोत्साहनों के महत्व को रेखांकित किया। मुरुगप्पा ग्रुप, टीआई क्लीन मोबिलिटी के कॉरपोरेट रिलेशंस के वरिष्ठ भागीदार एसओ त्यागी ने कहा कि ई-ट्रकों को प्रोत्साहित करने से भारत में उनके विकास और अपनाने में तेजी आएगी।

उपस्थित अन्य उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि देश का लगभग 18% प्रदूषण भारी परिवहन क्षेत्र से उत्पन्न होता है, जिससे पता चलता है कि स्वच्छ परिवहन नेटवर्क बनाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रक भारत के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे महंगे ईंधन आयात को कम करते हैं और शहरी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त ये वाहन देश के जलवायु उद्देश्यों के अनुरूप हैं, जो डीजल ट्रकों के लिए एक टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं।

विशेषज्ञों ने आगे कहा कि पीएम ई-ड्राइव योजना टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए। सरकार का सब्सिडी कार्यक्रम नवाचार को बढ़ावा देने और अधिक ट्रक ओईएम को इलेक्ट्रिक ट्रक उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है, जिससे अल्पावधि में ईंधन की खपत में संभावित 27% की कमी और 2030 तक 40% की कमी जैसे तत्काल लाभ हो सकते हैं। ऐसी सब्सिडी आंतरिक दहन इंजन ट्रकों और इलेक्ट्रिक विकल्पों के बीच 3x से 4x मूल्य अंतर को पाटने में मदद कर सकती है।

मांग सृजन के मोर्चे पर अमेज़न इंडिया के सार्वजनिक नीति प्रबंधक निखिल दहिया ने एक मजबूत ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। ओईएम प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि एक व्यापक राष्ट्रव्यापी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति, विशेष रूप से माल ढुलाई मार्गों पर क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रकों को आमतौर पर 100 किलोवाट से अधिक उच्च-शक्ति वाले चार्जर की आवश्यकता होती है, यदि अधिक निर्माताओं को इलेक्ट्रिक ट्रकों में निवेश करना शुरू करना है।

कार्यक्रम में विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भारत के ग्रिड के संरेखण पर चर्चा की तथा कहा कि वितरण ग्रिड अवसंरचना, ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार बिजली कटौती के कारण राजमार्गों पर अविश्वसनीय विद्युत गुणवत्ता से ग्रस्त है।

एमएचआई के सचिव कामरान रिज़वी ने कहा, "ई-ट्रक चरण अभी शुरू हुआ है और भारत वैश्विक स्तर पर ई-ट्रक बनाने वाले 5-6 देशों में से एक है।" उन्होंने कहा कि 2070 तक नेट ज़ीरो के लिए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, "निर्माताओं, खरीदारों और बैंकरों को एक साथ आना चाहिए ताकि तेज़ और सुचारू बदलाव सुनिश्चित हो सके।"

पीएम ई ड्राइव कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए सब्सिडी योजना के क्रियान्वयन के एक हिस्से के रूप में, भारत सरकार हरित भविष्य के लिए टिकाऊ परिवहन समाधान को बढ़ावा देने के लिए शिपर्स, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं और उद्योग जगत के नेताओं सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है।

इस बैठक का आयोजन भारी उद्योग मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद के सहयोग से किया था। इस कार्यक्रम में सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे।

ईवी अपनाने में चंडीगढ़ देश में नंबर 1

परिवहन विशेष न्यूज

चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में देश में नंबर 1 बन गया है। आंकड़ों के अनुसार हर 100 गाड़ियों में से शहर में 15 गाड़ियां ईवी बिक रही हैं। जबकि पंजाब में 100 गाड़ियों पर ईवी छह तो हरियाणा में महज चार हैं। इसके अलावा सरकारी व निजी घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने को लेकर तय किए गए लक्ष्य के भी करीब पहुंच चुका है।

यूटी प्रशासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के सचिव टीसी नौटियाल ने शुक्रवार, 15 नवंबर को चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में चंडीगढ़ की उपलब्धता पर एक प्रेजेंटेशन दी गई। इसमें चंडीगढ़ व अन्य राज्यों व यूटी में बिक रहे ईवी की तुलना की गई। शहर में ईवी अपनाने की दर अप्रैल से अक्तूबर 2024 तक 14.80 फीसदी है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है।

विभाग के आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ के बाद त्रिपुरा 14.79 फीसदी के साथ दूसरे नंबर पर है। गोवा में 12.63 फीसदी, असम में 11.15 फीसदी और उत्तर प्रदेश में 10 फीसदी है। पंजाब और हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में काफी पीछे हैं।

पंजाब में जहां ईवी अपनाने की दर 6.47 फीसदी है तो हरियाणा में महज 4.39 फीसदी है। बैठक में सचिव को बताया गया कि चंडीगढ़ में 20 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही सक्रिय हैं और पूरी तरह से चालू हैं। अगले सप्ताह तक 4 से 5 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन सक्रिय हो जाएंगे, जिससे शहर के इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे में के वृद्धि होगी।

सीसीपीए उत्पाद मानकों और सेवा को लेकर ओला इलेक्ट्रिक की जांच करेगी: रिपोर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, भारत की उत्पाद प्रमाणन एजेंसी, ओला इलेक्ट्रिक के मानकों की कमी और उत्पाद-संबंधी मुद्दों की जांच करेगी, उपभोक्ता मामलों के सचिव ने 14 नवंबर, 2024 को रॉयटर्स को बताया। अखबार ने बताया कि पिछले महीने सीसीपीए ने 10,000 शिकायतें मिलने के बाद स्पष्टीकरण मांगते हुए ई-स्कूटर निर्माता को नोटिस भेजा था। न्यूजवायर न्यूज के अनुसार, ओला ने कहा कि उसने 99.1% शिकायतों का समाधान कर दिया है। उस प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के बाद, सीसीपीए ने भारतीय मानक ब्यूरो से मामले की विस्तार से जांच करने को कहा है। इस मुद्दे पर रॉयटर्स को ओला इलेक्ट्रिक से समय पर जवाब नहीं मिल सका। अगस्त में शानदार लिस्टिंग के बाद बढ़ती शिकायतों और नियामक जांच ने ओला इलेक्ट्रिक को मुश्किल में डाल दिया है।

साइबर क्राइम क्या है? प्रकार, उदाहरण और रोकथाम

विजय गर्ग

"साइबर क्राइम" शब्द कंप्यूटर उद्योग और नेटवर्क में नवीनतम विकास के बाद पेश किया गया था। साइबर अपराधों को एक बड़ा जोखिम माना जाता है क्योंकि उनके वित्तीय नुकसान, संवेदनशील डेटा का उल्लंघन, सिस्टम की विफलता जैसे विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं, और यह किसी संगठन की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर सकता है। साइबर क्राइम क्या है? साइबर अपराध को ₹किसी भी गैरकानूनी कार्य को करने या करने में सहायता करने के लिए किसी भी संचार उपकरण का अवैध उपयोग₹ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साइबर अपराध को एक प्रकार के अपराध के रूप में समझाया जाता है जो नुकसान के उद्देश्य से एक नेटवर्क के तहत कंप्यूटर या कंप्यूटर के समूह को लक्षित या उपयोग करता है। साइबर अपराध कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके किए जाते हैं। वे व्यक्तियों, व्यावसायिक समूहों या यहां तक कि सरकारों को भी निशाना बना सकते हैं। जांचकर्ता उन उपकरणों की जांच करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं जिनके इस्तेमाल होने या साइबर अपराध का लक्ष्य होने का संदेह होता है। साइबर अपराधी कौन हैं? साइबर अपराधी वह व्यक्ति होता है जो प्रौद्योगिकी में अपने कौशल का उपयोग दुर्भावनापूर्ण कार्यों और अवैध गतिविधियों को करने के लिए करता है जिन्हें साइबर अपराध के रूप में जाना जाता है। वे व्यक्ति या टीम हो सकते हैं. साइबर अपराधी व्यापक रूप से ₹डार्क वेब₹ में उपलब्ध हैं, जहां वे ज्यादातर अपनी अवैध सेवाएं या उत्पाद प्रदान करते हैं। प्रत्येक हैकर साइबर अपराधी नहीं है क्योंकि हैकिंग को स्वयं अपराध नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग कमजोरियों को रिपोर्ट करने और उन्हें बैचने के लिए किया जा सकता है जिसे ₹व्हाइट हैट हैकर₹ कहा जाता है। हालाँकि, हैकिंग को एक साइबर अपराध माना जाता है जब इसका कोई हानिकारक गतिविधियों को संचालित करने का दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य होता है और हम इसे ₹ब्लैक हैट हैकर₹ या साइबर-अपराधी कहते हैं। साइबर अपराधियों के पास हैकिंग कौशल होना आवश्यक नहीं है क्योंकि सभी साइबर अपराधों में हैकिंग शामिल नहीं है। साइबर अपराधी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अवैध ऑनलाइन सामग्री का व्यापार कर रहे हों या घोटालेबाज या यहां तक कि ड्रग डीलर भी हो सकते हैं। तो यहां साइबर अपराधियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं: - ब्लैक हैट हैकर्स - साइबरस्टॉकर्स - साइबर आतंकवादी - घोटालेबाज लक्षित हमले करने वाले साइबर अपराधियों को थ्रेट एक्टर्स कहा जाना बेहतर है। साइबर अपराध कैसे होते हैं? साइबर अपराधी सिस्टम में पाए जाने वाले सुरक्षा छिद्रों और कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और लक्षित वातावरण में पैर जमाने के लिए उनका फायदा उठाते हैं। सुरक्षा छेद कमजोर प्रमाणीकरण विधियों और पासवर्ड का उपयोग करने का एक रूप हो सकता है, यह सख्त सुरक्षा मॉडल और नीतियों की कमी के कारण भी हो सकता है। साइबर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? दुनिया लगातार नई-नई तकनीक विकसित कर रही है, इसलिए अब उसकी निर्भरता तकनीक पर बहुत ज्यादा हो गई है। अधिकांश स्मार्ट डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इसके फायदे भी हैं और जोखिम भी हैं. जोखिमों में से एक साइबर अपराधों की संख्या में बड़ी वृद्धि है, इन प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा में मदद करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय और संचालन नहीं हैं। कंप्यूटर नेटवर्क साइबरस्पेस में लोगों को सेकंडों में दुनिया के किसी भी जुड़े हिस्से तक पहुंचने की अनुमति देता है। साइबर अपराधों के लिए एक देश से दूसरे देश में अलग-अलग कानून और नियम हो सकते हैं, यह भी उल्लेख करते हुए कि वास्तविक अपराधों के बजाय साइबर अपराध करते समय ट्रैक को कवर करना बहुत आसान होता है। हम साइबर अपराधों में बड़ी वृद्धि के विभिन्न कारणों को नीचे सूचीबद्ध कर रहे हैं: - कमजोर उपकरण: जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, कुशल सुरक्षा उपायों और समाधानों की कमी से कमजोर उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला सामने आती है जो साइबर अपराधियों के लिए एक आसान लक्ष्य है। - व्यक्तिगत प्रेरणा: साइबर अपराधी कभी-कभी किसी से बदला लेने के लिए साइबर अपराध करते हैंनफ़रत है या कोई समस्या है. - वित्तीय प्रेरणा: साइबर अपराधियों और हैकर समूहों की सबसे आम प्रेरणा, आजकल अधिकांश हमले इससे लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं। साइबर अपराध के दो मुख्य प्रकार - कंप्यूटर को निशाना बनाना इस प्रकार के साइबर अपराधों में हर संभव तरीका शामिल है जो कंप्यूटर उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है, उदाहरण के लिए मैलवेयर या सेवा से इनकार करने वाले हमले। - कंप्यूटर का उपयोग करना इस प्रकार में कंप्यूटर अपराधों के सभी वर्गीकरण करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग शामिल है। साइबर अपराधों का वर्गीकरण साइबर अपराधों को सामान्यतः चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 1. व्यक्तिगत साइबर अपराध: यह प्रकार व्यक्तियों को लक्षित कर रहा है। इसमें फ़िशिंग, स्पूफ़िंग, स्पैम, साइबरस्टॉकिंग और बहुत कुछ शामिल है। 2. संगठन साइबर अपराध: यहां मुख्य लक्ष्य संगठन हैं। आमतौर पर, इस प्रकार का अपराध अपराधियों की टीमों द्वारा किया जाता है जिसमें मैलवेयर हमले और सेवा से इनकार करने वाले हमले शामिल हैं। 3. संपत्ति साइबर अपराध: यह प्रकार क्रेडिट कार्ड या यहां तक कि बौद्धिक संपदा अधिकार जैसी संपत्ति को लक्षित करता है। 4. समाज साइबर अपराध: यह साइबर अपराध का सबसे खतरनाक रूप है क्योंकि इसमें साइबर-आतंकवाद भी शामिल है। सबसे आम साइबर अपराध अब जब आप समझ गए हैं कि साइबर अपराध क्या हैं, तो आइए कुछ सामान्य साइबर अपराधों पर चर्चा करें। 1. फ़िशिंग और घोटाला: फ़िशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है जो उपयोगकर्ता को लक्षित करता है और उपयोगकर्ता के बारे में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली संदेश और ईमेल भेजकर या दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करने और लक्ष्य प्रणाली पर इसका फायदा उठाने की कोशिश करके उन्हें धोखा देता है। 2. पहचान की चोरी पहचान की चोरी तब होती है जब कोई साइबर अपराधी किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर या व्यक्तिगत तस्वीरों का उपयोग धोखाधड़ी या अपराध करने के लिए उनकी अनुमति के बिना करता है। 3. रैनसमवेयर अटैक रैंसमवेयर हमले एक बहुत ही सामान्य प्रकार का साइबर अपराध है। यह एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को एन्क्रिप्ट करके सिस्टम पर उनके सभी व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने से रोकने की क्षमता रखता है और फिर एन्क्रिप्टेड डेटा तक पहुंच देने के लिए फिरौती मांगता है। 4. कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करना/दुरुपयोग करना यह शब्द निजी कंप्यूटर या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच और इसे बंद करके या संग्रहीत डेटा या अन्य अवैध तरीकों से छेड़छाड़ करके इसका दुरुपयोग करने के अपराध को संदर्भित करता है। 5. इंटरनेट धोखाधड़ी इंटरनेट धोखाधड़ी एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें इंटरनेट का उपयोग किया जाता है और इसे एक सामान्य शब्द माना जा सकता है जो इंटरनेट पर होने वाले सभी अपराधों जैसे स्पैम, बैंकिंग धोखाधड़ी, सेवा की चोरी आदि को समूहित करता है। साइबर क्राइम के अन्य प्रकार यहां अन्य 9 प्रकार के साइबर अपराध हैं: 1. साइबर बुलिंग इसे ऑनलाइन या इंटरनेट बुलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसी और के बारे में हानिकारक और अपमानजनक सामग्री भेजना या साझा करना शामिल है जो शर्मिंदगी का कारण बनता है और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बन सकता है। यह हाल ही में बहुत आम हो गया है, खासकर किशोरों के बीच। 2. साइबर स्टॉकिंग साइबरस्टॉकिंग को अवांछित लगातार कॉल और संदेशों जैसे नियंत्रण और डराने के उद्देश्य से अन्य व्यक्तियों को ऑनलाइन लक्षित करने वाली अवांछित लगातार सामग्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 3. सॉफ्टवेयर चोरी सॉफ़्टवेयर चोरी कॉपीराइट या लाइसेंस प्रतिबंधों के उल्लंघन के साथ भुगतान किए गए सॉफ़्टवेयर का अवैध उपयोग या प्रतिलिपि है। सॉफ़्टवेयर चोरी का एक उदाहरण तब होता है जब आप विंडोज़ की एक ताज़ा गैर-सक्रिय प्रतिलिपि डाउनलोड करते हैं और विंडोज़ सक्रियण के लिए वैध लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ₹क्रैकर₹ के रूप में जाना जाता है। इसे सॉफ़्टवेयर चोरी माना जाता है. न केवल सॉफ़्टवेयर को पायरेटेड किया जा सकता है बल्कि संगीत, फिल्में आदि को भी पायरेटेड किया जा सकता हैआर तस्वीरें. 4. सोशल मीडिया धोखाधड़ी किसी भी प्रकार की हानिकारक गतिविधियों को करने के लिए सोशल मीडिया फर्जी खातों का उपयोग करना जैसे अन्य उपयोगकर्ताओं का रूप धारण करना या डराने या धमकी भरे संदेश भेजना। और सबसे आसान और सबसे आम सोशल मीडिया धोखाधड़ी में से एक है ईमेल स्पैम। 5. ऑनलाइन नशीली दवाओं की तस्करी क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रौद्योगिकी के बड़े उदय के साथ, कानून प्रवर्तन का ध्यान आकर्षित किए बिना सुरक्षित निजी तरीके से धन हस्तांतरित करना और दवा सौदों को पूरा करना आसान हो गया। इससे इंटरनेट पर दवा विपणन में वृद्धि हुई। कोकीन, हेरोइन, या मारिजुआना जैसी अवैध दवाएं आमतौर पर ऑनलाइन बेची और कारोबार की जाती हैं, खासकर ₹डार्क वेब₹ के रूप में जानी जाने वाली साइट पर। 6. इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग इसे लेनदेन लॉन्ड्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह अज्ञात कंपनियों या ऑनलाइन व्यवसाय पर आधारित है जो स्वीकार्य भुगतान विधियां और क्रेडिट कार्ड लेनदेन करता है लेकिन अज्ञात उत्पादों को खरीदने के लिए अधूरी या असंगत भुगतान जानकारी देता है। यह अब तक के सबसे आम और आसान मनी लॉन्ड्रिंग तरीकों में से एक है। 8. साइबर एक्सटॉर्शन साइबर एक्सटॉर्शन साइबर अपराधियों द्वारा चुराए गए कुछ महत्वपूर्ण डेटा को वापस देने या सेवा हमलों से इनकार करने जैसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए पैसे की मांग है। 9. बौद्धिक संपदा का उल्लंघन यह कॉपीराइट और औद्योगिक डिज़ाइन जैसे किसी भी संरक्षित बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन या उल्लंघन है। 9. ऑनलाइन भर्ती धोखाधड़ी कम आम साइबर अपराधों में से एक जो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, वह है आवेदकों से वित्तीय लाभ प्राप्त करने या यहां तक कि उनके व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने के उद्देश्य से फर्जी कंपनियों द्वारा जारी किए गए फर्जी नौकरी के अवसर। साइबर अपराध के उदाहरण - रेविल और कासिया रैनसमवेयर रेविल एक रूसी या रूसी भाषी हैकिंग समूह है और इसे रैंसमवेयर-ए-ए-सर्विस ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। कसेया घटना जुलाई-2021 में हुई थी. यह घटना तब हुई जब कासिया की कंपनी का एक उत्पाद कासिया के ग्राहक नेटवर्क के अंतिम बिंदुओं पर प्रसिद्ध SODINOKIBI REvil रैंसमवेयर को तैनात कर रहा था, जिस पर दुनिया भर में कासिया के 1000 से अधिक ग्राहकों पर हमला किया गया था। कुछ घंटों बाद रेविल ने डार्क वेब पर अपनी हैप्पी ब्लॉग वेबसाइट पर पोस्ट करके हमले का श्रेय लिया और एक सार्वजनिक डिक्रिप्टर जारी करने के लिए 70 मिलियन डॉलर की फिरौती की मांग की, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह सभी क्षतिग्रस्त डिवाइसों को डिक्रिप्ट कर सकता है। हमला इतना प्रभावशाली था कि संयुक्त राज्य सरकार ने रेविल सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए कोई भी जानकारी देने वाले को 10 मिलियन डॉलर का इनाम देने की पेशकश की। स्रोत 22 साल के यूक्रेनी यारोस्लाव वासिंस्की पर हमले का संचालन करने और कासिया और अन्य कंपनियों के खिलाफ रैंसमवेयर फैलाने का आरोप लगाया गया था। - स्टक्सनेट स्टक्सनेट घटना एक प्रसिद्ध घटना है जो 2010 में हुई थी। स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म (मैलवेयर का प्रकार) का नाम है जो SCADA (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) सिस्टम को लक्षित करता है। स्टक्सनेट मैलवेयर ने ईरान के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विनाशकारी क्षति पहुंचाई। यह यूएसबी ड्राइव के माध्यम से फैल रहा था और मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करता था। मैलवेयर की कार्यक्षमता उन मशीनों की खोज करना थी जो पीएलसी (प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर) के रूप में काम कर रही हैं और यदि यह पाया गया तो मैलवेयर हमलावरों के माध्यम से इंटरनेट पर अपना कोड अपडेट कर देता है। - मैरियट होटल नवंबर 2018 में, मैरियट होटल समूह को बड़े पैमाने पर डेटा उल्लंघन का सामना करना पड़ा, जिससे 500 मिलियन से अधिक ग्राहक प्रभावित हुए। यह समझौता किसी अज्ञात पक्ष द्वारा अतिथि आरक्षण डेटाबेस के लिए हुआ। जो जानकारी थीलीक में ग्राहकों के लिए भुगतान जानकारी, मेलिंग पते, पासपोर्ट नंबर और फोन नंबर शामिल थे। मैरियट ग्रुप ने तुरंत सुरक्षा विशेषज्ञों के एक समूह के साथ घटना की जांच की और एक वेबसाइट और एक कॉल सेंटर स्थापित किया। उन्होंने प्रभावित ग्राहकों को ईमेल भी भेजे और उन्हें निगरानी उपकरणों तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जो इंटरनेट पर नज़र रखते हैं और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने का कोई सबूत मिलने पर अलर्ट देते हैं। - रॉकयू डेटा ब्रीच रॉकयू एक कंपनी है जो खेल के क्षेत्र में काम करती है और इसकी स्थापना 2005 में लांस टोकुडा और जिया शेन द्वारा की गई थी। दिसंबर 2009 तक कंपनी अच्छा काम कर रही थी, जिसे ₹अब तक का सबसे बड़ा डेटा उल्लंघन₹ कहा जाता है। डेटा उल्लंघन ने रॉकयू डेटाबेस से 32 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता खाते की जानकारी को उजागर और लीक कर दिया। कंपनी पासवर्ड को अनएन्क्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर कर रही थी, जिससे हैकर के लिए स्टोर किए गए सभी पासवर्ड तक पहुंच आसान हो गई। हैकर ने डेटाबेस से सभी डेटा लीक करने के लिए एक बहुत पुरानी और लोकप्रिय SQL भेद्यता का उपयोग किया। इस बड़े उल्लंघन के बाद, लीक हुए पासवर्डों का कुल सेट प्रवेश परीक्षण में एक बहुत ही सहायक संसाधन बन गया क्योंकि हैकर्स खातों और उत्पादों की सुरक्षा और पासवर्ड ताकत का परीक्षण करने के लिए पासवर्ड की इस वर्डलिस्ट का उपयोग करते हैं। आप इस आलेख में शीर्ष डेटा उल्लंघनों के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं। साइबर अपराध को कैसे रोकें? खुद को और अपने पर्यावरण को साइबर अपराधों के जोखिम से बचाने के लिए कई सुझाव और दिशानिर्देश हैं जैसे: 1. सुनिश्चित करें कि आप एंटीवायरस और फ़ायरवॉल जैसे नवीनतम सुरक्षा सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। 2. अपने परिवेश के लिए सर्वोत्तम संभव सुरक्षा सेटिंग्स और कार्यान्वयन लागू करें। 3. अविश्वसनीय वेबसाइटें ब्राउज़ न करें और अज्ञात फ़ाइलें डाउनलोड करते समय सावधान रहें, और ईमेल अनुलग्नक देखते समय भी सावधान रहें। 4. मजबूत प्रमाणीकरण विधियों का उपयोग करें और अपने पासवर्ड को यथासंभव मजबूत रखें। आप इस लेख में अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखने के टिप्स पा सकते हैं। 5. संवेदनशील जानकारी ऑनलाइन या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा न करें। 6. अपने बच्चों को इंटरनेट के उपयोग के जोखिमों के बारे में शिक्षित करें और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें। 7. साइबर अपराध का शिकार होने पर पुलिस का हवाला देकर तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए हमेशा तैयार रहें।

शिक्षा बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: 2025 के लिए भविष्यवाणी

अपना चेहरा बदल रही है। परिणामस्वरूप, शिक्षा बाजार में एआई में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव होना तय है। नवीन शिक्षण उपकरण और छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करने की प्रेरणा एआई को एक शिक्षा गेम चेंजर बनाती है, क्योंकि के-12 संस्थान और उच्च शिक्षा भूमि नए, छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह लेख अनुमानित विकास, अनुप्रयोग के मुख्य क्षेत्रों और निरंतरता की पड़ताल करता है जो 2025 तक शिक्षा बाजार में एआई को आकार देगा। शिक्षा में एआई की अनुमानित बाजार वृद्धि अगले कुछ वर्षों में, शिक्षा बाजार में एआई में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है। उद्योग विश्लेषण के अनुसार, 2025 तक इसका मूल्य दसियों अरबों तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि एआई टूल को अपनाने, व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों की बढ़ती मांग और डिजिटलीकरण और भौतिक और दूरस्थ शिक्षा से दूर होने के कारण है। शिक्षा पर महामारी के प्रभाव ने एआई-संचालित समाधानों के लिए दरवाजे खोल दिए और दुनिया भर के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में जुड़ाव बढ़ाने, सीखने की खाई को पाटने और लक्षित शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए एआई की क्षमताओं में नई रुचि जगाई। एआई की मांग में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि शैक्षणिक संस्थान विभिन्न शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने और शैक्षणिक परिणामों का विस्तार करने के लिए एआई को मौलिक रूप से आवश्यक मानते हैं। शिक्षा में एआई के मुख्य कार्यक्षेत्र 1. अनुकूली शिक्षा और वैयक्तिकृत शिक्षा वैयक्तिकृत शिक्षण ने एआई की सामग्री लेने और उसे छात्र की गति और सीखने की शैली के अनुरूप बनाने की क्षमता का उपयोग करके सामग्री वितरण के बारे में हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। एआई सिस्टम एक छात्र

हैं। इसे K-12 और उच्च शिक्षा दोनों पर लागू करने से उच्च शैक्षणिक मानकों को बनाए रखते हुए छात्र की अपनी गति से प्रगति की सुविधा मिलेगी। 2. एआई-संचालित ट्यूशन और आभासी सहायता एआई-संचालित ट्यूटरिंग की हालिया अवधारणा की बदौलत सीखने का समर्थन पहले से कहीं अधिक सुलभ है। एआई ट्यूटर किसी भी समय जटिल विषयों में मदद करते हैं, छात्रों को मुख्य बिंदुओं को याद रखने में मदद करते हैं और विषयों में उनकी स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हैं। वर्चुअल ट्यूटर्स और एआई-संचालित प्लेटफॉर्म सवालों के जवाब दे सकते हैं, और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, जहां पारंपरिक शिक्षण वातावरण कम पड़ता है, वहां इसे जारी रखा जा सकता है। 3. माता-पिता और शिक्षक की सहभागिता में वृद्धि यह माता-पिता और शिक्षकों को एक छात्र की शैक्षणिक प्रगति, सामाजिक भावनात्मक विकास और उन्हें किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, इसकी गहराई से जांच करने का अधिकार देता है। एआई सिस्टम से नियमित अपडेट और प्रगति रिपोर्ट के साथ शिक्षक और अभिभावक डेटा आधारित निर्णय ले सकते हैं, जिसका अर्थ यह भी है कि छात्रों की प्रगति को जोखिम में नहीं डाला जाएगा। 4. एआर और वीआर के माध्यम से इमर्सिव लर्निंग इंटरैक्टिव आभासी वास्तविकता (वीआर) और संवर्धित वास्तविकता (एआर) अनुभव के माध्यम से सीखना कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव बनाया गया है। छात्र विषयों का गहराई से पता लगाने के लिए वर्चुअल फील्ड यात्राएं, 3डी सिमुलेशन और इमर्सिव लैब गतिविधियां करने में सक्षम हैं और व्यस्त और जिज्ञासु रहेंगे। एआई द्वारा सक्षम ऐसे उपकरण, महत्वपूर्ण सोच के साथ-साथ समस्या निवारण कौशल को विकसित करने में योगदान करते हैं,

प्रदान करके पारिवारिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। विस्तृत प्रगति रिपोर्ट तक पहुंच के साथ, माता-पिता अपने बच्चे की शिक्षा में सक्रिय रूप से लगे रह सकते हैं, जिससे बेहतर शैक्षणिक स्कोर और बेहतर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्राप्त होगी। 2. निरंतर अपस्किलिंग और रीस्किलिंग भविष्य के नौकरी बाजार के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग प्रमुख प्राथमिकताएं बन गई हैं। एआई-संचालित पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्रों को उद्योग की मांगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में मदद करते हैं। चूंकि तकनीक-प्रेमी पेशेवरों की मांग बहुत अधिक है, इसलिए ये कार्यक्रम छात्रों को भविष्य की नौकरी भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं। 3. प्रारंभिक हस्तक्षेप और लक्षित समर्थन एआई का वास्तविक समय विश्लेषण छात्रों को पिछड़ने से रोकने के लिए शुरुआती हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है। एआई संघर्षरत शिक्षार्थियों की पहचान कर सकता है और सीखने में अंतराल बढ़ने से पहले शिक्षकों को लक्षित रणनीतियों को लागू करने में मदद कर सकता है। 2025 तक, शिक्षा में एआई का पूर्वानुमानित विश्लेषण अकादमिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए अधिक सटीक, सक्रिय हस्तक्षेप प्रदान करेगा। 4. शिक्षण को सीखने की सुविधा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है एआई उपकरण शिक्षकों की भूमिका को पारंपरिक शिक्षण से हटाकर सीखने को सुविधाजनक बनाने की ओर ले जा रहे हैं। केवल ज्ञान प्रदान करने के बजाय, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे, जिससे छात्रों को एआई-संचालित प्लेटफार्मों पर नेविगेट करने में मदद मिलेगी जो महत्वपूर्ण सोच और स्वतंत्र शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। यह बदलाव छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप है, जहां शैक्षणिक विकास को एआई

बेहतर बनाने के बारे में डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि के साथ, माता-पिता अपने बच्चे की शिक्षा में शामिल रह सकते हैं। यह बेहतर शैक्षणिक स्कोर और सामाजिक और भावनात्मक सीखने की अनुमति देता है। निरंतर अपस्किलिंग और रिस्किलिंग निरंतर अपस्किलिंग और रीस्किलिंग अब भविष्य के नौकरी बाजार के लिए स्कूलों का फोकस बन गया है। एआई-संचालित पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्रों को आवश्यक कौशल प्राप्त करने और उद्योग की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करते हैं। भविष्य की नौकरी की भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए और तकनीक-प्रेमी पेशेवरों की बढ़ती आवश्यकताओं वाली नौकरियों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें तैयार करने का यह एक अच्छा तरीका है। प्रारंभिक हस्तक्षेप और लक्षित समर्थन एआई का वास्तविक समय विश्लेषण समय पर हस्तक्षेप की अनुमति देता है ताकि छात्रों को पिछड़ने से पहले समर्थन मिल सके।

शिक्षकों द्वारा संघर्षरत शिक्षार्थियों की शीघ्र पहचान करके और लक्षित रणनीतियों को लागू करके व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। 2025 तक शिक्षा में एआई के पूर्वानुमानित विश्लेषण अकादमिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अधिक सटीक, सक्रिय हस्तक्षेप प्रदान करेंगे। शिक्षण को सीखने की सुविधा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है शिक्षा में, एआई उपकरण पारंपरिक शिक्षण भूमिकाओं को सुविधाजनक भूमिकाओं में बदल देते हैं। शिक्षक केवल ज्ञान बांटकर नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं: महत्वपूर्ण सोच कौशल के साथ एआई-संचालित प्लेटफार्मों के माध्यम से अपने छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। इसे छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया है जहां छात्र स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, जबकि शैक्षणिक विकास को समर्थन मिलता है। 2025 में K-12 एजुकेशन AI संचालित प्रमुख उपकरण 2025 तक शिक्षा बाजार में कई एआई-संचालित उपकरण लोकप्रिय होने की उम्मीद है, जिसमें अनुकूली शिक्षा और वैयक्तिकृत फीडबैक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। प्रमुख उपकरणों में शामिल हैं: सेंचुरी टेक: इस उपकरण को अनुकूली शिक्षण के रूप में जाना जाता है जो छात्र की प्रगति के आधार पर वैयक्तिकृत मार्गों को बढ़ावा देता है जो जुड़ाव और प्रतिधारण को बढ़ाते हैं। न्यूटन अल्टा: यह वास्तविक समय फीडबैक लूप पर केंद्रित ओ के साथ लक्षित अभ्यास की अनुमति देता हैn दृष्टिगत गहन विषयों, उदाहरण के लिए, गणित और विज्ञान के लिए विशिष्ट सीखने के अंतराल। क्वेरियम: एसटीईएम ट्यूशनिंग में विशेषज्ञता वाले एआई-आधारित टूल के रूप में, यह छात्रों के लिए कठिन अवधारणाओं को समझने में आसान बनाने के लिए वैयक्तिकृत है। स्मार्ट स्पैरो: एक बहुमुखी उपकरण जो वैयक्तिकृत निर्देश का समर्थन करता है: शिक्षक प्रत्येक सीखने के स्तर के अनुरूप वैयक्तिकृत पाठ बना सकते हैं। एआई को शिक्षकों और उनके छात्रों दोनों के लिए एक वरदान के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये उपकरण जोड़े को शैक्षणिक सफलता हासिल करने में भागीदार बनाते हैं। एआई-आधारित शैक्षिक उपकरण अपने परिष्कार के कारण एक ऐसा सीखने का माहौल विकसित करेंगे जो मजबूत हो और जो प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। बाज़ार संचालक और चुनौतियाँ ड्राइवर: शिक्षा बाजार की वृद्धि में एआई नवीन शिक्षा समाधानों की बढ़ती मांग, डिजिटल साक्षरता को आगे बढ़ाने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलों से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा डिजिटल परिवर्तन एक बड़ा विकास चालक बना रहा, जिसे COVID-19 महामारी ने बढ़ावा दिया, जिसने लगभग दुनिया भर में इसे तेज और सुविधाजनक बनाया। एआई अब केवल एक प्रचलित शब्द नहीं रह गया है; वास्तव में, शिक्षक व्यक्तिगत शिक्षण को सक्षम करने के साथ-साथ संसाधन अनुकूलन में सुधार के लिए एआई की क्षमता के बारे में तेजी से जागरूक हो रहे हैं। चुनौतियाँ: शिक्षा बाजार में एआई बढ़ रहा है, लेकिन चुनौतियाँ सामने आ रही हैं: गोपनीयता, नैतिकता और तकनीकी विभाजन का जोखिम। स्थिति को बदतर होने से बचाने के लिए एआई संचालित शिक्षा उपकरणों को सभी के लिए समान रूप से सुलभ बनाना महत्वपूर्ण होगा। विश्वास और जवाबदेही बनाए रखने के लिए, स्कूलों और संस्थानों को सीखने में एआई के नैतिक पक्ष, विशेष रूप से डेटा संग्रह और एल्गोरिथम पारदर्शिता पर भी ध्यान देना चाहिए। भविष्य का आउटलुक शिक्षा बाजार में एआई के आगे बढ़ने के साथ भविष्य में स्कूलों में एआई के उपयोग के लिए आसान और अधिक विशिष्ट समय का वादा किया गया है। 2025 तक, एआई दुनिया भर की कक्षाओं में एक मानक पेशकश बन जाएगी, जिसमें विभिन्न सीखने के अवसरों की अनूठी पेशकश और व्यक्तिगत छात्रों की विभिन्न सीखने की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। यह एआई संचालित विकास K-12 संस्थानों, उच्च शिक्षा प्रदाताओं और शैक्षिक तकनीकी कंपनियों को महान मूल्य प्रदान करने के लिए तैयार है, जबकि छात्र खुद को अधिक व्यक्तिगत, लचीले और आकर्षक सीखने के अनुभव में पाएंगे। इसलिए, एआई प्रौद्योगिकियों को अपनाने से सीखने के अनुभव में सुधार हो सकता है और शिक्षार्थियों को डिजिटल पहली दुनिया में सीखने में मदद मिल सकती है। शिक्षा बाजार में एआई की भविष्य की सफलता नवाचार और समावेशिता का सही संतुलन खोजने पर निर्भर करेगी, सीखने के संसाधनों की अगली पीढ़ी उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए आसानी से सुलभ होनी चाहिए। अंत में, आने वाले वर्षों में एआई शिक्षा के लिए पूरी तरह से बदलाव की चिंगारी बन जाएगा: सीखने का प्रतिमान पूरी तरह से 2025 के क्षितिज में वैयक्तिकरण, पहुंच और नवाचार पर आधारित होगा।

विजय गर्ग

सोचना बनाम करना

आम आदमी इन दिनों बहुत कुछ सोचने लगा है। आजादी से पहले के दिनों में आम जिंदगी की जरूरतों से इतर या उसके समांतर सोचने का एक लक्ष्य था। उस लक्ष्य में आजादी सबसे प्राथमिक थी। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सामने कुछ स्पष्ट मार्ग थे और साथ थे महान मार्गदर्शक, संस्कार और उसूल। इसके अलावा भी बहुत कुछ, जिससे अपने वजूद का बेहतरीन अहसास होता था। एक नई आत्मसंतुष्टि का भी आभास होता था। कई लोग तो हंसते-हंसते खुद को बलिदान कर देते थे। अपना सब कुछ न्योछावर कर देते थे। आज यकीन नहीं होता कि हम उन्हीं बलिदानियों के बाद की पीढ़ी के हैं। कई बार यह सोच कर शर्मिंदगी होती है कि ऐसे लोग भी हैं यहां कि सिर्फ एक कागज को इधर से उधर करने के लिए अलग से कुछ पैसे सामने वाले से हथिया लेते हैं। वरना उनका काम रुक जाता है। हजारों योजनाओं के हजारों लाख रुपए कहां चले जाते हैं, पता नहीं चलता। हम ही असमानता से बिखरने लगे थे, लेकिन पैसों का केंद्रीकरण सिर्फ कुछ लोगों के पास हो गया।

इन दिनों खुद पर पड़ने वाली नजरें भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हम कुछ लोलुप नजरों में महज 'वोट' बनकर रह गए हैं, जहां हम उपभोग में लाए जाते हैं स्वार्थवश। हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसलिए उन्ही संबंधों की भावनाओं को लेकर उनके पास वोट मांगने जाते हैं और उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। हमारी उन लोगों के प्रति प्रतिबद्धताएं ज्यादा हैं और लगभग रोज उन्हीं से टकराना है। ऐसे में हम उन्हें बड़े नेताओं की तरह बहला-फुसला नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ की नजरों में हम उन बड़ी-बड़ी कंपनियों के लुभावने दावों से प्रभावित होने वाले 'ग्राहक' भर हैं, जो अपना सामान बेचने के लिए तमाम भावनाएं लूट लेते हैं। 'मुफ्त वाले माल' को नकारने वाले आदर्श को अपनाते - अपनाते हम 'एक के साथ दो मुफ्त' वाले आदर्श अपना बैठे हैं। अपने ऊपर से बोझ हल्का करने के लिए हम यह भी सोचते हैं कि 'तह के अंदर भी हाल वही है, जो तह के ऊपर हाल, मछली बचकर जाए कहां जब जल ही सारा जाल।'

हम बाबा खड़गसिंह की उस कहानी के बारे में भी सोचते हैं, जहां से विश्वास का संकट शुरू हुआ था। अब हमारे मध्य विश्वास इतना पुराना हो चला है कि उसे हाशिये पर करने के लिए हमने उसके लिए 'वृद्धाश्रम' खोल दिए हैं और उन्हीं में वह अपना निर्वासित जीवन जी रहा है। हम सोचते हैं उस निरीह आदमी के बारे में जो हमारी आंखों के सामने अविश्वास का शिकार होकर खाली हाथ लौट जाता है, जो हो सकता है विश्वास करने योग्य हो। धर्म से लेकर कर्म क्षेत्र और परिवार से लेकर बाजार, सभी तरफ संदेह के आगोश में लिपटकर अविश्वास हमारी भावनाओं की बहुमंजिला इमारतों में बने फ्लैटों में रहने लगा है। विश्वास का संकट गांव में भी बढ़ा है, लेकिन सुसभ्य और संपन्न शहर की तुलना में आज भी गांव लाख दर्जे अच्छे हैं। गांव का कोई व्यक्ति यह कहता हुआ मिल जा सकता है कि विश्वास आपस में कम हुआ है, लेकिन शहरी आदमी पर विश्वास सहजता से कर पाना मुश्किल हो गया है। जबकि गांव के लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ऐसे वाकये गांव वालों के साथ अक्सर देखे जा सकते हैं, जिनमें शहरियों ने उन्हें धोखा दिया। पंचायत के ज्यादातर काम-काज विश्वास पर ही होते हैं। सोचने का मसला यह भी है कि जिस आदमी को शासक बनना था, वह इधर-उधर की खाक छान रहा है। जिसे वास्तव में वैज्ञानिक होना था, वह मजदूरी कर रहा है। जिसे वास्तव में इंजीनियर बनना था, वह कहीं बैठा दिहाड़ी पर 'वेल्डिंग' कर रहा होता है। जिसे मौका मिलना था आगे बढ़ने का, वह बेरोजगारी का शिकार होकर हाथ बांधे बैठा है। हजारों युवाओं को देश के रचनात्मक आंदोलन में हिस्सेदार होना था, वे सब बेरोजगार बैठे हैं या फिर गलत व्यसनों - व्यवसायों से जुड़ रहे हैं। प्रतिभाओं का मूल्यांकन और उन्हें मंच मिलना सिर्फ शहर तक सीमित रह गया है, जबकि गांव में भी विभिन्न खेलों से लेकर अन्य शिक्षणेतर गतिविधियों में ग्रामीण प्रतिभाएं कमतर नहीं हैं।

समाज के प्रतिष्ठित और प्रतिनिधित्व करने वाले शख्स से समाज के प्रति प्रतिबद्धता की आशा की जाती है, क्योंकि वे अपने अनुजों के लिए 'आदर्श' होते हैं। लेकिन अफसोस कि उनमें से अधिकतर बिखरे हुए व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। हम इस बारे में भी सोच लेते हैं कि सिर्फ स्कूल-कालेज जाने से ही 'शिक्षा' प्राप्त हो जाती है। जबकि तमाम डिग्रियों से लदे लोग भी आज ऐसे कार्य करते हैं कि उनकी शिक्षा पर बड़ा प्रश्नचिह्न लग जाता है। किसी स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त व्यक्ति से संबंधित विषय के बारे में पूछने पर निराशा हाथ लग सकती है। जो शिक्षा हमें सतही ज्ञान भर दे जाती है और तनावों, विचलनों पर विजय पाना नहीं सिखाती है, उस पर हम गर्व करते हैं। गांव में रहने वाले लोगों को अक्सर 'गंवई' करार दिया जाता है। दरअसल, हम 'एसी' की ठंडक में बैठे यह सोच लेते हैं कि 'अ' से 'द' तक के गरीबों को फलां समस्या है और 'ई' से 'फ' तक के किसानों को फलां समस्या है। जबकि आज भी आबादी के एक बड़े हिस्से को सिर्फ एक वक्त का भोजन नसीब होता है। देखा जाए तो हम सिर्फ सोचते ज्यादा रहे हैं। सपनों में ही ज्यादा खोते रहे हैं। इसलिए शायद हकीकत का धरातल उथला रह गया। हम हर चीज तोड़ते-फोड़ते रहे, शासकीय संपत्ति को बेगाना समझते रहे। प्रतिफल यह रहा कि हम आवरण से देश प्रेम के गीत, बातें तो करते रहे, पर हम यह नहीं सोच पाए कि हमें सिर्फ सोचना नहीं है, कुछ करना भी है।

पाकिस्तान की खस्ता हालत का एक और सबूत, कतर और अबू धाबी से PIA को खरीदने की गुजारिश

परिवहन विशेष न्यूज

पाकिस्तान मंदी और नकदी की कमी का सामना कर रहा है। ऐसे में इसने देश के राष्ट्रीय एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) को बेचने या निजीकरण करने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय एयरलाइन की निजीकरण करने के लिए एक बोली भी मिली थी जिसे सरकार ने खारिज कर दिया। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरलाइन की बिक्री के लिए कतर या अबू धाबी से बातचीत कर रहा है।

नई दिल्ली। पाकिस्तान मंदी का सामना कर रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) को बेचने की कोशिश को तेजी कर दिया है। पिछले हफ्ते आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के निजीकरण के लिए केवल एक ही बोली मिली थी। यह बोली सरकार की उम्मीद से काफी कम रही। जिसे अब सरकार ने खुद खारिज कर दिया।

अब PIA के निजीकरण को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार अब कतर या अबू धाबी इस एयरलाइन को खरीद सकते हैं। हालांकि, अभी तक इसको लेकर कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

पाकिस्तान सरकार के पास नहीं होगा अधिकार

पाकिस्तान सरकार के पास पीआईए पूरी हिस्सेदारी थी। अब सरकार राष्ट्रीय एयरलाइन में 51-100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश कर रही है। इस साल की शुरुआत से एयरलाइन की हिस्सेदारी की बिक्री शुरू हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एयरलाइन की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 10 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई।

पाकिस्तान का न्यूज चैंनल एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार जी2जी एग्रीमेंट के तहत विदेशी सरकार को राष्ट्रीय एयरलाइन की हिस्सादरी बेचने का प्लान बना रहा है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कतर या अबू धाबी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की हिस्सेदारी खरीद सकता है। अगर कतर या अबू धाबी पीएआई को खरीद लेते हैं तो पाकिस्तान सरकार के पास PIA का अधिकार खत्म हो जाएगा।

पाकिस्तान सरकार ने कतर या अबू धाबी से बातचीत करना शुरू कर दिया है। अब माना जा रहा है कि पूर्व-निर्धारित नियमों और शर्तों की मदद से दोनों देशों के बीच बातचीत में तेजी आ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि कतर 2 अरब डॉलर में पीएआई खरीदने में "रुचि" दिखाई है।

राष्ट्रीय एयरलाइन की निजीकरण के लिए पाकिस्तान निजीकरण मंत्री फवाद हुसैन फवाद ने कतर अधिकारी से बातचीत करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच बिक्री के लिए बैठक भी चल रही है।

क्यों बिक रहा पीआईए

देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक योजना शुरू की थी। पीएआई की हिस्सेदारी भी इस योजना के तहत बेची जा रही है। इस योजना में 80 से ज्यादा सरकारी उद्यमों को बेचने की योजना है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने निजीकरण मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि 13 नवंबर 2024 को पाकिस्तान सरकार ने पीआईए के लिए आई आखिरी बोली को खारिज कर दिया। पीएआई के लिए आखिरी बोली 60 फीसदी हिस्सेदारी के लिए आया था। यह बोली 36 मिलियन डॉलर यानी 10 अरब पाकिस्तानी रुपए के लिए लगाई गई थी। रियल एस्टेट फर्म ब्लू वर्ल्ड सिटी ने पीएआई को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। पाकिस्तान सरकार ने इस बोली को खारिज कर दिया क्योंकि यह सरकार के न्यूनतम मूल्य से काफी कम था।

पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन घाटे का सामना कर रही है। पिछले दो दशकों में एयरलाइन को 3.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा का घाटा हुआ है। ऐसे में अब यह एयरलाइन कर्ज में डूब गई है। एयरलाइन के घाटे की वजह ज्यादा कर्मचारियों और भ्रष्टाचार को माना जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर 2023 के नौ महीने में राष्ट्रीय एयरलाइन को 75 बिलियन पीकेआर का घाटा हुआ। ऐसे में पाकिस्तान पहले ही नकदी की कमी का सामना कर रही है। ऐसे में अब सरकार ने राष्ट्रीय एयरलाइन को बेचने के प्रयास को तेज कर दिया है।

क्या फिर से एमआरएफ बनेगा महंगा शेयर, लगातार 4 दिन से एल्सीड निवेश में लग रहा लोअर सर्किट

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। स्टॉक मार्केट में बिकवाली भरे कारोबार से निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस नुकसान भरे कारोबार का असर भारतीय शेयर बाजार के सबसे महंगे शेयर पर भी देखने को मिला है।

इंडियन स्टॉक मार्केट में Elcid Investments ने अक्टूबर में सबसे महंगे शेयर का दर्जा हासिल किया था। इसके बाद से इस शेयर की खूब चर्चा होने लगी। इस शेयर के बढ़ते भाव ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। दरअसल, जून 2024 में इस कंपनी के एक शेयर की कीमत 3.53 रुपये थी। वहीं अक्टूबर के अंत में इसकी कीमत 2.5 लाख रुपये प्रति शेयर हो गई।

अब कंपनी के शेयर की दोबारा चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि पिछले चार सत्रों से निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, पिछले चार कारोबारी दिनों से कंपनी के शेयर में 5 फीसदी का लोअर सर्किट लग रहा है। इस वजह से कंपनी के शेयर की कीमत 63,000 रुपये से ज्यादा घट गई।

अब कितनी है एक शेयर की कीमत

स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार Elcid Investments शेयर का 52 वीक हाई 332,399.95 रुपये है। कंपनी ने यह भाव 8 नवंबर 2024 को टच किया था। इसके बाद 11 नवंबर से 14 नवंबर तक स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट आया। जिसके बाद 14 नवंबर को इसका भाव 269172.70 रुपये प्रति शेयर हो गया।

अब कौन है सबसे महंगा शेयर

भारतीय शेयर बाजार में अभी भी सबसे महंगे शेयर का खिताब Elcid Investments के पास ही है। Elcid Investments के एक शेयर की कीमत 2,69,172.70 रुपये है। वहीं, एमआरएफ के 1,20,601 रुपये प्रति शेयर है।

29 अक्टूबर 2024 से Elcid Investments शेयर की खूब चर्चा हो रही थी। इस दिन Elcid Investments ने MRF के स्टॉक को पीछे छोड़कर सबसे महंगे शेयर का खिताब हासिल किया। 29 अक्टूबर 2024 को Elcid Investments शेयर का बॉम्बे स्टॉक एक्चेंज (BSE) पर स्पेशल नीलामी सत्र हुआ था। इस सत्र में कंपनी के शेयर 2,36,250 रुपये के भाव पर पहुंच गए। इस सत्र के बाद कंपनी के शेयरधारक रातोंरात में करोड़पति बन गए।

क्यों महंगा है ये शेयर

Elcid Investments निवेश वाली कंपनी है। यह कंपनी अलग-अलग कंपनी में निवेश करके पैसे कमाती है। इस कंपनी का मुख्य संपत्तियों में से एक एशियन पेंट्स (Asian Paints) हैं। Elcid Investments के पास एशियन पेंट्स की 2.83 फीसदी हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 8,500 करोड़ रुपये है।

पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना है आसान, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

पीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? रिटायरमेंट के बाद पेंशन और एकमुश्त राशि का लाभ मिले इसके लिए कई कर्मचारी ईपीएफओ में निवेश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि रिटायरमेंट से पहले ही निकासी करनी पड़ती है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप किन स्थिति में आंशिक निकासी कर सकते हैं और उसका पूरा प्रोसेस क्या है।

नई दिल्ली। कभी भी कोई परेशानी बता कर नहीं आती है। ऐसे में हम पहले से इमरजेंसी फंड तैयार रखते हैं पर कई बार हमें अतिरिक्त आर्थित सहायता की जरूरत होती है। इस स्थिति में हम उधार लेने से पहले इन्वेस्टमेंट फंड का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड में पीएफ अकाउंट ( ) भी शामिल होता है। हम अपनी रिटायरमेंट के बाद इनकम को जारी रखने के लिए यह फंड तैयार करते हैं, लेकिन कई बार हमें रिटायरमेंट से पहले इसमें से निकासी करनी पड़ सकती है।

हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप पीएफ अकाउंट से कब-कब निकासी कर सकते हैं और अकाउंट से पैसे विड्रॉल करने का तरीका क्या है।

कब निकाल सकते हैं पूरा पैसा

पीएफ अकाउंट में आप पूरा पैसा रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेंबर लगातार दो महीने बेरोजगार रहता है तब भी वह पूर्ण निकासी कर सकता है। हालांकि, पहले महीने बेरोजगार रहने पर पीएफ अकाउंट से केवल 75 फीसदी ही निकासी कर सकते हैं।

ईपीएफओ (EPFO) मेंबर को आंशिक निकासी की भी सुविधा मिलती है। कई परिस्थिति में आंशिक निकासी की जा सकती है। हालांकि, इसके लिए मेंबर को उनसे जुड़े दस्तावेज के साथ अप्लाई करना होता है।

कब कर सकते हैं आंशिक निकासी

- मेडिकल इमरजेंसी
- खुद की या परिवार में किसी की शादी होने पर
- होम लोन (Home Loan) के पेमेंट के लिए
- घर खरीदने या घर की मरम्मत करवाने के लिए
- अगर ईपीएफ मेंबर लगातार पांच साल तक योगदान देता है तब ही वह आंशिक निकासी कर सकता है।

आंशिक निकासी के लिए कैसे करें अप्लाई

सबसे पहले यूएएन पोर्टल पर जाकर यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।

- अब आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी और स्क्रीन पर शो हो रहे कैप्चा को दर्ज करें।
- इसके बाद ईपीएफओ मेंबर की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी।
- अब 'ऑनलाइन सेवाएं' में जाकर 'क्लेम' पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके अपने डिटेल्स को वेरिफाई करना होगा।
- अब सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग फॉर्म में हां पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें। अब आपको क्लेम से संबंधित सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- क्लेम के लिए आपको फॉर्म 15G के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स दर्ज करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद क्लेम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा।

क्लेम रिक्वेस्ट करने के बाद लगभग 10 दिन के बाद बैंक अकाउंट में राशि आ जाएगी। आप पोर्टल पर जाकर अपने क्लेम को ट्रैक भी कर सकते हैं।

इन निवेशकों के लिए बढ़ गया अलॉटमेंट का चांस, क्या आपको मिलेगा फायदा या नहीं

शेयर बाजार में एनटीपीसी (NTPC) की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी (NTPC Green Energy IPO) का आईपीओ आने वाला है। इस आईपीओ में कई निवेशकों के लिए अलॉटमेंट के चांस बढ़ गए हैं। वहीं कई निवेशकों को इस बार भी रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में निवेश करना होगा। इस आर्टिकल में जानते हैं कि किन निवेशकों को फायदा पहुंचेगा।

नई दिल्ली। स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए आईपीओ काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। बाजार में इस हफ्ते एनटीपीसी कंपनी की सहायक कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। निवेशक काफी लंबे समय से इस आईपीओ का इंतजार कर रहे थे।

NTPC Green Energy की पेरेंट कंपनी NTPC Ltd. है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ (NTPC Green Energy IPO) 19 नवंबर 2024 से निवेश के लिए खुलेगा। इस आईपीओ में अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो हम आपको निवेश से पहले ही बताएंगे कि आईपीओ अलॉटमेंट का चांस कितना है।

इन निवेशकों को होगा फायदा

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ में शेयरधारकों के लिए शेयरधारक कोटा (Shareholder Quota) भी है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास एनटीपीसी का एक शेयर है वह शेयरधारक कोटा के तहत आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ में शेयरधारकों के लिए 10 फीसदी शेयरधारक कोटा (Shareholder Quota) आरक्षित रखा गया है। ऐसे में शेयरधारक कोटा के तहत आईपीओ में निवेश करने पर अलॉटमेंट का चांस बढ़ जाता है।

अब सवाल आता है कि क्या सोमवार को शेयर खरीदने पर आईपीओ अलॉटमेंट का चांस बढ़ेगा या नहीं। आपको बता दें कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने RHP में बताया कि जिन निवेशकों के डीमैट अकाउंट में 13 नवंबर तक शेयर होंगे वह ही शेयरहोल्डर कोटा के तहत आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप सोमवार को शेयर खरीदते हैं तो आपको शेयरधारक कोटा का फायदा नहीं मिलेगा।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में (NTPC Green Energy IPO Details)

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ टोटल 10,000 करोड़ रुपये का है। यह आईपीओ 19 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 22 नवंबर 2024 को बंद हो जाएगा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड (NTPC Green Energy IPO Price Band) 102-108 रुपये तय किया है। इसके अलावा आईपीओ का लॉट साइज 138 शेयर का है।

यह पूरा आईपीओ फ्रेश इश्यू है। इसका मतलब इसमें ऑफर फॉर सेल के तहत शेयर की बिक्री नहीं होगी। इस आईपीओ के जरिये कंपनी 92.59 करोड़ इक्विटी जारी कर रही है।

ट्रेवल इंश्योरेंस है काम की चीज! झूठी बम धमकी के कारण टल गई फ्लाइट तब नुकसान के लिए कर सकते हैं क्लेम

फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि कभी भी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) जरूर लें। ट्रैवल इंश्योरेंस कई स्थिति में कामगार साबित होता है। अगर कभी बम की आशंका के कारण फ्लाइट कैंसिल या टल जाती है तो इस स्थिति में ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत क्लेम कर सकते हैं। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। आज के समय में अक्सर हमें एक खबर सुनने को मिलती है और वो है बम धमकियां। अब भले ही यह धमकियां झूठी होती है, लेकिन इसका असर पैसेंजर पर सीधा पड़ता है। जी हां, जब भी इस प्रकार की धमकियां आती है तो फ्लाइट कैंसिल या फिर पोस्टपॉन्ड हो जाती है। अब इस तरह की परेशानी में यात्री नुकसान की भरपाई की मांग करते हैं।

अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या इस स्थिति में एयरलाइन नुकसान की भरपाई करेगा या नहीं। अगर एयरलाइन इसकी भरपाई नहीं करता है तो क्या इस समय ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) काम आता है। हम आपको इस आर्टिकल में इन सवालों का जवाब देंगे।

कौन करेगा नुकसान की भरपाई

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के निर्देशों के अनुसार फ्लाइट के लेट होने या फिर कैंसिल होने पर एयरलाइन भोजन, वैकल्पिक उड़ान या फुल टिकट रिफंड की व्यवस्था करता है। यह भरपाई तब होती है जब मौसम या फिर किसी दूसरी वजह से फ्लाइट लेट या कैंसिल होती है। अगर असाधारण घटनाओं जैसे बम की आशंका होती है तो एयरलाइन पैसेंजर को हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता है।

इस स्थिति में ट्रैवल इंश्योरेंस राहत दे सकता है। इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस की पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बम की धमकी के कारण फ्लाइट लेट या डाइवर्ट होती है को पैसेंजर रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं।

क्लेम में कितनी राशि मिलती है

इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस में 4 लाख रुपये तक का कवरेज मिलता है। इसमें कंपनियां बड़े मुआवजा देती है। अगर ट्रिप डिले हो जाती है तो कंपनी 4200 से 84 हजार रुपये तक का मुआवजा देती है। वहीं किसी इमरजेंसी हो जाने पर होटल में रुकने के लिए 4 लाख रुपये तक का कवरेज देती है। इसी तरह अगर पैसेंजर को यात्रा के दौरान कोई परेशानी आती है तब कंपनी प्रति दिन 10,500 रुपये तक का अलाउंस भी ऑफर करती है। यह सभी कवरेज इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी के नियमों पर आधारित होता है।

ट्रैवल इंश्योरेंस की प्रीमियम राशि डेस्टिनेशन, कवरेज, कवर्ड व्यक्ति की उम्र, इंश्योरेंस कंपनी आदि पर निर्भर करता है। इसके अलावा यात्रा खर्च का 10 फीसदी तक का इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है। अगर आप भी कोई ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं तो पहले आपको कई कंपनियों की पॉलिसी को कम्पेयर करना चाहिए। इसके बाद सभी नियमों व शर्तों को पढ़ने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए।

शेयर बाजार के साथ गिर रहा सोने का भाव, वेडिंग सीजन में क्यों घट रही पीले की कीमत

वेडिंग सीजन में सोने की मांग बढ़ जाती है जिसकी वजह से इनकी कीमतों में तेजी आती है। लेकिन अभी चल रहे वेडिंग सीजन के बीच सोने की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। ऐसे में सवाल आता है कि सोने की कीमतों में किस वजह से गिरावट आ रही है। आइए इस आर्टिकल में इसका जवाब जानते हैं।

नई दिल्ली। वेडिंग सीजन में सोने की डिमांड में तेजी आती है। ऐसे में इनके भाव भी बढ़ जाते हैं। लेकिन, इस साल इसका उल्टा हो रहा है। पिछले चार दिनों में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार में जब भी गिरावट आती है तो सोने की कीमतों (Gold Price) में तेजी आती है। लेकिन, अभी शेयर बाजार में गिरावट के साथ सोने की कीमतों में भी गिरावट आई है। पिछले कुछ समय से सोने की कीमतों में सर्राफा बाजार के साथ ग्लोबल मार्केट में नरमी देखने को मिली है।

क्या है सोने की कीमत (Gold Price)

पिछले चार सत्रों से सोने की कीमतों में गिरावट आ रही है। 24 कैरेट गोल्ड जिसे 99.9 फीसदी शुद्ध माना जाता है वह 77,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 22 कैरेट गोल्ड 76,650 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है। चांदी 2,310 रुपये की गिरावट के साथ 90,190 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

शेयर बाजार के साथ सोना और चांदी में आई गिरावट के कारण अब निवेशक भी चिंता में है। दरअसल, कुछ समय पहले माना जाता था कि शेयर बाजार में जब गिरावट आती है तो सोने की कीमतों में तेजी आती है। ऐसे में निवेशक बाजार से निकासी करके गोल्ड में निवेश करते थे। लेकिन, अब सोने की कीमतों में गिरावट ने निवेशकों को असंजस में डाल दिया है। हम आपको बताएंगे कि आखिर सोने की कीमतों में गिरावट क्यों आ रही है।

मजबूत हो रहा अमेरिकी डॉलर

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार अमेरिकी चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिकी मुद्रा डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि जब भी डॉलर मजबूत होता है तो कीमती धातु जैसे सोने और चांदी निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाती है। इस स्थिति में बहुमूल्य धातुओं की डिमांड कम हो जाती है, जिस वजह से उनकी कीमतों में नरमी आती है।

ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद

फेड ने इस महीने ही दूसरी बार ब्याज दरों (Fed Rate Cut) में कटौती की थी। यह कटौती आगे भी जारी रह सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के विश्लेषक जतिन त्रिवेदी के अनुसार अगर अमेरिका में महंगाई दर 2 फीसदी के करीब रहती है तो ब्याज दर में कटौती हो सकती है। ब्याज दर में कटौती होने की उम्मीद से सोने की कीमतों पर दबाव आता है। ऐसे में सोने में निवेश बढ़ता है लेकिन कीमत घट जाती है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस: स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक - पत्रकार पंकज जैन

आगरा,संजय साग़र सिंह। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर ताज़ प्रेस क्लब के सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार पंकज जैन ने प्रेस और मीडिया के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस दिन का महत्व बताते हुए कहा कि 16 नवम्बर को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के बाद से यह दिन भारतीय पत्रकारिता की स्वतंत्रता और ज़िम्मेदारी को समर्पित है।

पंकज जैन ने कहा, ₹राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व को लेकर समाज में जागरूकता फैलाना है। भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है और निष्पक्ष पत्रकारिता एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

उन्होंने आगे कहा, ₹प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है और इसके प्रतिनिधियों की भूमिका जनकल्याण में अभूतपूर्व होती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी प्रेस ने अहम योगदान दिया था और आज नए भारत के निर्माण में भी मीडिया की सक्रिय भूमिका है।

पंकज जैन ने पत्रकारों की मेहनत और निष्ठा की सराहना करते हुए कहा, ₹आपकी सत्यनिष्ठा, निर्भीकता और निस्वार्थ सेवा के लिए हम आपको नमन करते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में आपका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने में आपकी भूमिका सराहनीय है।

उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को भी रेखांकित किया और कहा, ₹स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक मूल तत्व है। मीडिया पर बिना किसी डर या पक्षपात के काम करने की जिम्मेदारी है, ताकि लोकतंत्र के संरक्षक और प्रवर्तक के रूप में उसका कार्य निर्भीक और निष्पक्ष हो।₹

अंत में, पंकज जैन ने सभी पत्रकार बंधुओं को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, ₹आप सभी लोकतंत्र के सजग प्रहरी और सत्य के निष्ठावान साधक हैं, और इस दिन हम आपकी निर्भीक पत्रकारिता को सलाम करते हैं।"

अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने में राज्यसरकार बिफल : सपा

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ कोटिया, महानदी, पोलावरम, बंसधारा जल विवाद को सुलझाने में कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही ओडिशा के हितों के खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी के ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष शिव हाथी यादव ने कहा कि वर्तमान में ओडिशा और केंद्र में 'डबल इंजन' की सरकार है, जबकि विवाद में शामिल राज्य में एनडीए सरकार भी सत्ता में है; इसलिए विवाद आसानी से सुलझने की बजाय दिन-ब-दिन धीमा होता जा रहा है।

इन चार महत्त्वपूर्ण अंतरराज्यीय विवादों को नवीन सरकार के समय से कानूनी जाल में फसा हुआ है। इस सम्बंध में राज्य को भारी मात्रा में अर्थ खर्चा करना पड़राहा है। जहाँ आंध्र प्रदेश के साथ तीन विवाद, कोटिया, पोलावरम मामला और बंसधारा जल विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, वहीं ओडिशा सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हालाँकि कानूनी टीम और सरकारी अधिकारी वर्षों से लंबित चार मामलों में अदालत में पेश हो रहे हैं, लेकिन ओडिशा सरकार और राज्य के लोगों को अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है।

कोटिया विवाद को सुलझाने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर मूल मामले (2/2023) की सुनवाई 17 अक्टूबर को हुई थी। राज्य सरकार ख़ुद सुनवाई से अनुपस्थित थी। ओडिशा सरकार ने 19 जनवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 को निरस्त करने की मांग की, जो कोटिया विवाद के समाधान में बाधा है। 29 जुलाई, 2024 को ओडिशा सरकार ने मूल याचिका में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव दायर किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के केंद्रीय बजट भाषण में पोलावरम परियोजना का निर्माण जल्द पूरा करने की घोषणा की। इसमें ओडिशा के मलकानगिरी जिले में बैकवाटर से उत्पन्न समस्या के समाधान का ज़िक्र नहीं किया गया। मॉनसून सीजन ख़त्म होने के बाद 1 नवंबर से पोलावरम परियोजना का निर्माण तेज कर दिया गया है। अब प्रोजेक्ट का करीब 77 फीसदी काम पूरा हो चुका है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि परियोजना का निर्माण मार्च 2028 तक पूरा हो जाएगा। मामले की आखिरी सुनवाई 21 फरवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर, 2022 को समाधान करने का निर्देश दिया था। एक माह के अंदर विवाद राजनीतिक स्तर पर या मुख्यमंत्री की बैठक में सुलझाने की कोर्ट राय को कार्यकारी करने में डबल इंजिन सरकार की कोई दिलचस्पी नेही दिखरही है।

दो साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री की बैठक नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। ओडिशा सरकार ने पिछले 21 महीनों में इस मामले की त्वरित सुनवाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। मामले की सुनवाई नहीं हो पाने का सीधा फायदा आंध्र को हो रहा है। केंद्र ने आंध्र सरकार को ख़ुश करनेके लिए ओड़िशा को मोहरा बनाय है। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का पद न्यायमूर्ति ए.एम. के इस्तीफे के बाद से 8 महीने से खाली है। खांडिलाकर। केंद्र सरकार ने अभी तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 12 मार्च 2018 को महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। पिछले छह साल में ट्रिब्यूनल में सिर्फ़ एक गवाह की सुनवाई हुई है। चेयरपर्सन की अनुपस्थिति ने मामले की आगे की सुनवाई को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट में बंसधारा जल विवाद मामले की सुनवाई 16 जुलाई, 2024 को हुई। अगली सुनवाई 10 दिसम्बर को होनी है। कुल मिलाकर, ओडिशा सरकार को राजनीतिक समाधान या अदालतों के माध्यम से कानूनी समाधान के बीच चयन करना होगा। ये चार अहम मामले। कानूनी समाधान के लिए, एक स्वतंत्र कानूनी टीम द्वारा त्वरित सुनवाई के लिए बार-बार अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहिए जिसे करने में डबल इंजिन सरकार बिफल रही है। इसी तरह, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भाजपा और आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार बनने से राजनीतिक समस्याओं के समाधान के बजाय भाजपा सरकार का ओडिशा विरोधी रवैया स्पष्ट हो रहा है।

आ-का-मा-भै, उच्चारण के साथ उड़ीसा सीमा से बंगाल सीमा तक 'बैंत बंदाण'

कार्तिक कुमार परिच्छा , स्टेट हेड

सरायकेला। प्राचीन कलिंग की नौ वाणिज्यिक ऐतिहासिक- धार्मिक उत्सव बोईत बंदाण झारखंड के तीनों सिंहभूम जिले में ओडिया भाषियों द्वारा मनाया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर झारखंड के तीनों सिंहभूम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा डुबकी लगायी गई एवं बालुका पूजा की गयी। मनोहरपुर से सटे राउरकेला सीमा से बहरागोड़ा बंगाल के मिदनापुर जिले के सीमा तक जलाशयों में केले के बने नौकाओं का पूजन सहित हिलाओं द्वारा स्नान के पश्चात बालूका पूजा भी की। इससे पूर्व महिलाओं द्वारा बालुका के समीप आकर्षित रंगोली बनाई, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके अग्रज बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की आकृति आंकी गई।

ऐतिहासिक परंपरा का निर्वाह किया:-

कभी कलिंग ,कोदोंग,ओड्र उत्कल,तोषाली के नाम से जाने वाला भू भाग रहा आधुनिक ओडिशा, उसकी सीमाएं गोदावरी से गंगा तक रही पांच सौ वर्ष पूर्व तो कलिंग कभी ग्यारह राज्य तथा बारह देशों तक फैला था। जहां उसकी गवाही आज भी सामुद्रिक व्यापार का यह उत्सव देता है। आज ओडिया हर जगह यह उत्सव मनाता है। इसी क्रम में झारखंड के तीनों सिहभूम जिलों पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में उड़ीसा तक यह उत्सव मनाया गया।

इस दिन श्रद्धालुओं ने केले के तने में बने नाव को जल में प्रवाहित कर

'आ, का मां, भै' उच्चारण किया करते। जिसका सीधा मतलब जावा, बाली, सुमात्रा, वर्णेय (अब इंडोनेशिया) तत्कालीन द्विपो के नाम से जूड़ा है। इन्हीं द्विपो में कभी सामुद्रिक व्यापार चलता था ओडिशा का। पूर्णिमा में कार्तिक स्नान के साथ समूचे सिंहभूम के उड़िया लोगों ने इलाके के मंदिरों में भगवान का दर्शन किया। विशेष कर जगन्नाथ मंदिरों एवं शिवालयों में गहमागहमी भीड़ रही।

सरायकेला में मांजन घाट शिव मंदिर, कुदरसाई शिव मंदिर तथा जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। 'बोईतो बंदाणी" उत्सव के दौरान महिलाओं ने सुबह खरकाई नदी में स्नान करते हुए केले के तने से बनी नाव (बोईतो) को जल में प्रवाहित किया। उनके साथ वे महिलाएं भी उत्सव में शामिल रही जो समूचे कार्तिक महीना में उपवास रख कर भोर चार बजे से बालुका में राई दामोदर पूजन किया करती थी। इसमें पिंकी रथ, मुनु कवि, अर्पणा दाश, जान देवी, प्रिति, हनी , खुशी, मनू, प्रतिमा, मानी, मालती मोहान्ति , रिंकी मोहान्ति , ललीता मोहान्ती , रीना, तपु, उर्मिला, लीली, बेबी , सुरमा , रूबी, मोनिका, तरंगिनि महापात्र आदि शामिल रहे।

नवजातों की जिंदगियां हो गई राख़।

45 बचे, दस नवजात बेकसूर खाक,
किसे दोष दे हम किसका था हाथ।
झांसी प्रशासन जांच में जुटा जरूर,
रोते बिलखते भी अभिभावकों का,
आप कैसे करोगे उनका दु:ख दूर।

45 बचे, दस नवजात बेकसूर खाक,
किसे दोष दे हम किसका था हाथ।
हर माँ ने नौ महीने किया था इंतज़ार,
लाऊंगी मैं पालना करूंगी खूब प्यार!
देखो लापरवाही से ख्वाब हुआ तार-तार।

45 बचे, दस नवजात बेकसूर खाक,
किसे दोष दे हम किसका था हाथ।
क्या होगा जांच से हम पर हुआ वज्रपात,
कैसे सह पाएंगे हम इतना बड़ा आघात!
आँगन में खुशियां पाने जागे कितनी रात।

45 बचे, दस नवजात बेकसूर खाक,
किसे दोष दे हम किसका था हाथ।
ये देखों नवजात आग के हवाले हुए,
नन्हें बच्चों की जिंदगियां हो गई राख़।

संजय एम. तराणेकर

उड़ती भारत की बेटियां..।

आगे बढ़तीं, नहीं वह किसी से डरतीं
सपनों को वह बुनतीं
पंख फैलाकर आसमान में,
उड़ती भारत की बेटियाँ।
अपने भारत को खुशहाल बनाती,
देश को सम्मान दिलाती
कठिनाईयों में भी वह निडर होकर,
आगे बढ़तीं भारत की बेटियाँ।
वह पुरुषों से कम नहीं,
हर एक परिस्थिति में बार निकलना
जानती है
दु:ख-दर्द-तकलीफ़ में वह
दवा बन जाती हैं भारत की बेटियाँ।
दुर्गा काली स्वरूपा वह,
रानी लक्ष्मीबाई व अहिल्या बन
समय आने पर हाथों में तलवार,
उठा लेती हैं भारत की बेटियाँ।
नहीं किसी से कम,
उनमें है बहुत दम
वह अबला नहीं है
हैं सबला भारत की बेटियाँ।
आज कन्धे से कन्धा मिलाकर,
चल रहीं हर एक क्षेत्र में।
अपना सिक्का जमा रहीं हैं
हर ओर भारत की बेटियाँ॥

हरिहर सिंह चौहान

बाजारीकरण की भेंट चढ़े हमारे सामाजिक त्यौहार

हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। त्योहार हमको सामाजिक और संस्कारिक रूप से जोड़ने का काम करते हैं। हमारी सांस्कृतिक और संस्कारिक एकता ही भारत की अखंडता का मूल आधार है। "व्रत-त्योहारों के दिन हम देवताओं का स्मरण करते हैं, व्रत, दान तथा कथा श्रवण करते हैं, जिससे व्यक्तिगत उन्नति के साथ सामाजिक समरसता का संदेश भी समाज में पहुँचता है। इसमें ही भारतीय संस्कृति के बीज छिपे हैं।" हमारे सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिनसे मात्र एक व्यक्ति, या परिवार ही नहीं वरन पूरा समाज आनंदित और उल्लासित होता है। भारत को यदि पर्व-त्योहारों का देश कहा जाए तो उचित होगा। यहाँ भोजपुरी भाषा में एक कहावत है-'सात वार नौ त्यौहार'।

-डॉ० सत्यवान सौरभ

कृषि प्रधान होने के कारण प्रत्येक ऋतु-परिवर्तन हंसी-ख़ुशी मनोरंजन के साथ अपना-अपना उपयोग रखता है। इन्हीं अवसरों पर त्योहार का समावेश किया गया है, जो उचित है। प्रथम श्रेणी में वे व्रतोत्सव, पर्व-त्योहार और मेले है, जो सांस्कृतिक हैं और जिनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों और विचारों की रक्षा करना है। इस वर्ग में हिन्दूओं के सभी बड़े-बड़े पर्व-त्योहार आ जाते है, जैसे-होलिका-उत्सव, दीपावली, बसन्त, श्रावणी, संक्रान्ति आदि। संस्कृति की रक्षा इनकी आत्मा है। दूसरी श्रेणी में वे पर्व-त्योहार आते है, हिन्हें किसी महापुरूष की पुण्य स्मृति में बनाया गया है। जिस महापुरूष की स्मृति के ये सूचक है, उसके गुणों, लीलाओं, पावन चरित्र, महानताओं को स्मरण रखने के लिए इनका विधान है। इस श्रेणी में रामनवमी, कृष्णाष्टमी, भीष्म-पंचमी, हनुमान-जयंती, नाग-पंचमी आदि त्योहार रखे जा सकते है।

यानि यहाँ हर दिन में एक त्योहार अवश्य पड़ता है। अनेकता में एकता की मिसाल इसी त्योहार पर्व के अवसर पर देखी जाती है। रोजमर्रा की भागती-दौड़ती, उलझनों से भरी हुई ऊर्जा प्रधान हो चुकी, वीरान-सी बनती जा रही ज़िन्दिगी में ये त्योहार ही व्यक्ति के लिए सुख, आनंद, हर्ष एवं उल्लास के साथ ताज़गी भरे पल लाते हैं। यह मात्र हिंदू धर्म में ही नहीं वरन विभिन्न धर्मों, संप्रदायों पर लागू होता है। वस्तुत: ये पर्व विभिन्न जन समुदायों की सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं और पूर्व संस्कारों पर आधारित होते हैं। सभी त्योहारों की अपनी परंपराएँ, रीति-रिवाज होते हैं। ये त्योहार मानव जीवन में करुणा, दया, सरलता, आतिथ्य सत्कार, पारस्परिक प्रेम, सद्भावना, परोपकार जैसे नैतिक गुणों का विकास कर मनुष्य को चारित्रिक एवं भावनात्मक बल प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति के गौरव एवं पहचान ये पर्व, त्योहार सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं।

सामाजिक त्योहार और अंतर-विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास और पारस्परिक कौशल के निर्माण में सहायता करने के लिए अद्भुत अवसर प्रदान करते हैं। पारस्परिक कौशल में दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और बातचीत करने की क्षमता शामिल है और आत्मविश्वास स्वयं और स्वयं की क्षमताओं में विश्वास है, जो दोनों दूसरों के साथ सकारात्मक सम्बंध बनाने के लिए आवश्यक हैं। इस लेख में, हम कुछ तरीकों पर ग़ौर करेंगे कि ये आयोजन बच्चों के आत्मविश्वास और पारस्परिक कौशल को बनाने में कैसे मदद करते हैं। सामाजिक त्योहार विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के संपर्क में लाते हैं, जो उनके क्षितिज को व्यापक बना सकते हैं और उन्हें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद कर सकते हैं। नए दोस्त और संपर्क बना सकते हैं, जो समुदाय से अधिक जुड़ाव महसूस करने और अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद कर सकते हैं। ये आयोजन इसे विकसित करने का एक शानदार तरीका है क्योंकि वे बहुत सारे लोगों को एक साथ लाते हैं और इस तरह एकता और भाईचारे की भावना पैदा करते हैं। ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के प्रति अधिक स्वीकार्य, सहिष्णु और समावेशी होना सिखाते हैं।

बाजारीकरण ने सारी व्यवस्थाएँ बदल कर रख दी है। हमारे उत्सव-त्योहार भी इससे अछूते नहीं रहे। शायद इसीलिए प्रमुख त्यौहार अपनी रंगत खोते जा रहे हैं और लगता है कि हम त्यौहार सिर्फ़ औपचारिकताएँ निभाने के लिए मनाये जाते हैं। किसी के पास फुरसत ही नहीं है कि इन प्रमुख त्योहारों के दिन लोगों के दुख दर्द पूछ सकें। सब धन कमाने की होड़ में लगे हैं। गंदी हो चली राजनीति ने भी त्योहारों का मज़ा किरकिरा कर दिया है। हम सैकड़ों साल गुलाम रहे। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इन त्योहारों की रंगत कभी फीकी नहीं पड़ने दी। आज इस अर्थ युग में सब कुछ बदल गया है। कहते थे कि त्यौहार के दिन न कोई छोटा और न कोई बड़ा। सब बराबर। लेकिन अब रंग प्रदर्शन भर रह गये हैं और मिलन मात्र औपचारिकता। हम त्यौहार के दिन भी हम अपनो से, समाज से पूरी तरह नहीं जुड़ पाते। जिससे मिठाइयों का स्वाद कसैला हो गया है। बात तो हम पूरी धरा का अँधेरा दूर करने की करते हैं, लेकिन ख़ुद के भीतर व्याप्त अंधेरे तक को दूर नहीं कर पाते। त्योहारों पर हमारे द्वारा की जाने वाली इस रस्म अदायगी शायद यही इशारा करती है कि हमारी पुरानी पीढ़ियों के साथ हमारे त्यौहार भी विदा हो गये।

हमारे पर्व त्यौहार हमारी संवेदनाओं और परंपराओं का जीवंत रूप हैं जिन्हें मनाना या यूँ कहें की बार-बार मनाना, हर साल मनाना हर समाज बंधु को अच्छा लगता है। इन मान्यताओं, परंपराओं और विचारों में हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनगिनत सरोकार छुपे हैं। जीवन के अनोखे रंग समेटे हमारे जीवन में रंग भरने वाली हमारी उत्सवधर्मिता की सोच मन में उमंग और उत्साह के नये प्रवाह को जन्म देती है। हमारा मन और जीवन दोनों ही उत्सवधर्मी है। हमारी उत्सवधर्मिता परिवार और समाज को एक सूत्र में बाँधती है। संगठित होकर जीना सिखाती है। सहभागिता और आपसी समन्वय की सौगात देती है। हमारे त्योहार, जो हम सबके जीवन को रंगों से सजाते हैं, सामाजिक त्यौहार एक अनूठा मंच प्रदान करते हैं इनमे साथियों के साथ सहयोग करने, मिलने और सामूहीकरण करना, अपनी प्रतिभा दिखाने और विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में सिखाने और सीखने की क्षमता होती है। ये कौशल हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और अक्सर हमारे जीवन के लगभग सभी पहलुओं के मूल में होते हैं।

इसलिए, वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता का जहाँ तक प्रश्न है, व्रत-त्यौहारों के दिन हम उक्त देवता को याद करते हैं, व्रत, दान तथा कथा श्रवण करते हैं जिससे व्यक्तिगत उन्नति के साथ सामाजिक समरसता का संदेश भी दिखाई पड़ता है। इसमें भारतीय संस्कृति के बीज छिपे हैं।" पर्व त्योहारों का भारतीय संस्कृति के विकास में अग्रतिम योगदान है। भारतीय संस्कृति में व्रत, पर्व-त्यौहार उत्सव, मेले आदि अपना विशेष महत्व रखते हैं। हिंदुओं के ही सबसे अधिक त्यौहार मनाये जाते हैं, कारण हिन्दू ऋषि-मुनियों के रूप में जीवन को सरस और सुन्दर बनाने की योजनाएँ रखी है। प्रत्येक पर्व-त्यौहार, व्रत, उत्सव, मेले आदि का एक गुप्त महत्व है। प्रत्येक के साथ भारतीय संस्कृति जुडी हुई है। वे विशेष विचार अथवा उद्देश्य को सामने रखकर निश्चित किये गये हैं। मूल्यों को पुन: प्रतिष्ठा के लिए मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। मूल्यपरक शिक्षा आज समय की मांग बन गई है। अत: इसे शीघ्रातिशीघ्र लागू करने की आवश्यकता है। वर्तमान डिजिटल युग में लोग अपनी सभ्यता-संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसके कारण व्रत तथा त्यौहार का महत्व बढ़ जाता है।

(42वीं जन्म-जयंती पर विशेष)

युवा शक्ति के प्रतीक एवं प्रेरणा-स्रोत आईपीएस मनुमुक्त 'मानव', जिन्हें एक दशक बाद भी भुला पाना संभव नहीं

मनुमुक्त के पिता डॉ. रामनिवास 'मानव' भरे मन से बताते हैं कि अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही और मनुमुक्त की मृत्यु के षड्यंत्र में शामिल उनके बैचमेट अफसरों की संलिप्तता के दस्तावेजी सबूतों के बावजूद, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि तेलंगाना पुलिस और सीबीआई ने इसे सामान्य घटना बताकर मामले को रफा-दफा कर दिया। तेलंगाना पुलिस और सीबीआई का पूरा प्रयास दोषियों को बचाने का था, दोषियों को सजा दिलाने का नहीं। यही नहीं, मनुमुक्त को ट्रेनी बताकर सभी सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया, किसी ने एक रुपये की भी आर्थिक सहायता परिवार को प्रदान नहीं की।

-प्रियंका सौरभ

नियति का यह कैसा दुखद विधान है कि विशिष्ट प्रतिभाओं को यहाँ अत्यल्प जीवन ही मिलता है। आदि शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, श्रीनिवास रामानुजन, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रांगेय राघव तक, एक लंबी सूची है ऐसे महापुरुषों की, जो अपनी चमक बिखेरकर अल्पायु में ही इस दुनिया से विदा हो गए। भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी मनुमुक्त 'मानव' भी एक ऐसे ही प्रतिभा-पुंज थे, जिन्हें काल ने असमय ही अपना ग्रास बना लिया।

28 अगस्त, 2014 को बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अत्यंत होनहार और प्रभावशाली पुलिस अधिकारी मनुमुक्त की 30 वर्ष, 9 माह की अल्पायु में नेशनल पुलिस अकेडमी, हैदराबाद (तेलंगाना) के स्विमिंग पूल में डूबने से, संदिग्ध परिस्थितियों में, मृत्यु हो गई थी। स्विमिंग पूल के पास ही स्थित ऑफिसर्स क्लब में चल रही विदाई पार्टी के बाद, आधी रात को जब मनुमुक्त का शव स्विमिंग पूल में मिला, तो अकेडमी में ही नहीं, पूरे देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह अकेडमी के 66 वर्ष के इतिहास में घटित होने वाली पहली इतनी बड़ी दुर्घटना थी। यहीं यह बताना भी आवश्यक है कि इतनी मर्मांतक और दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी के बाद भी इस मामले की न तो ठीक-से जांच हुई और न ही किसी अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की गई। मनुमुक्त के पिता डॉ. रामनिवास 'मानव' भरे मन से बताते हैं कि अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही और मनुमुक्त की मृत्यु के षड्यंत्र में शामिल उनके बैचमेट अफसरों की संलिप्तता के दस्तावेजी सबूतों के बावजूद, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि तेलंगाना पुलिस और सीबीआई ने इसे सामान्य घटना बताकर मामले को रफा-दफा कर दिया। तेलंगाना पुलिस और सीबीआई का पूरा प्रयास दोषियों को बचाने का था, दोषियों को सजा दिलाने का नहीं। यही नहीं, मनुमुक्त को ट्रेनी बताकर सभी सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया, किसी ने एक रुपये की भी आर्थिक सहायता परिवार को प्रदान नहीं की।

उल्लेखनीय है कि मनुमुक्त 2012 बैच और हिमाचल प्रदेश काडर के परम मेधावी और ऊर्जावान पुलिस अधिकारी थे। 23 नवंबर, 1983 को हिसार (हरियाणा) में जन्मे तथा पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से उच्च शिक्षा प्राप्त मनुमुक्त ने 'सी' सर्टिफिकेट सहित एनसीसी की सभी सर्वोच्च उपलब्धियाँ प्राप्त की थीं। वह बहुत अच्छे चिंतक होने के साथ-साथ बहुमुखी कलाकार और सफल फोटोग्राफर भी थे; सेल्फी के तो मास्टर ही थे। उनकी समाज-सेवा में भी बड़ी रुचि थी। वह अपने दादा-दादी की स्मृति में अपने पैतृक गाँव में स्वास्थ्य-केंद्र तथा नारनौल में सिविल सर्विस एकेडमी स्थापित करना चाहते थे। देश और समाज के लिए उनके और भी बहुत सारे सपने थे, जो उनकी असामयिक मृत्यु के साथ ही ध्वस्त हो गए।

इकलौते जवान आईपीएस बेटे की मृत्यु मनुमुक्त के पिता, वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद् डॉ. रामनिवास 'मानव' तथा माता अर्थशास्त्र की पूर्व प्राध्यापिका डॉ. कांता भारती के लिए भयानक वज्रपात से कम नहीं थी। कोई अन्य दम्पत्ति होता, तो शायद टूटकर बिखर जाता, लेकिन 'मानव' दम्पत्ति ने अद्भुत धैर्य और साहस का परिचय देते हुए, न केवल इस अकल्पनीय-असहनीय पीड़ा को झेला, बल्कि अपने बेटे की स्मृतियों को सहेजने और सजीव बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास भी प्रारंभ कर दिए। उन्होंने अपनी संपूर्ण जमापूंजी लगाकर 10 अक्टूबर, 2014 को मनुमुक्त 'मानव' मेमोरियल ट्रस्ट का गठन किया और नारनौल में 'मनुमुक्त भवन' का निर्माण कर उसमें वातानुकूलित लघु सभागार, संग्रहालय और पुस्तकालय की स्थापना की। ट्रस्ट द्वारा अढाई लाख का एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, एक लाख का एक राष्ट्रीय पुरस्कार, 21-21 हज़ार के दो तथा 11-11 हज़ार के तीन राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सौ मनुमुक्त 'मानव' स्मृति-सम्मान प्रारंभ किए। दोनों बड़े पुरस्कार फिलहाल स्थगित हैं, किंतु शेष सभी पुरस्कार-सम्मान प्रतिवर्ष, नियमित रूप से, प्रदान किए जा रहे हैं। 'मनुमुक्त भवन' में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम भी निरंतर चलते रहते हैं, जिनमें अब तक भारत के अतिरिक्त जापान, फीजी, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, तुर्की, रूस, मॉरिशस, कोस्टारिका, अमेरिका, कनाडा आदि दो दर्जन देशों की लगभग पांच सौ विशिष्ट विभूतियाँ सहभागिता कर चुकी हैं। ट्रस्ट द्वारा ऑन लाइन आयोजित कार्यक्रमों में तो 55-60 देशों के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार, फ़िल्मिकार, शिक्षाविद्, समाजसेवी, पर्यावरणविद्, खिलाड़ी, पर्वतारोही, प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता जुड़ चुके हैं तथा यह सिलसिला अब भी जारी है। मात्र सात वर्ष की अल्पावधि में ही, अपनी उपलब्धियों के कारण, नारनौल का 'मनुमुक्त भवन' अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। ट्रस्ट द्वारा 15 अगस्त, 2021 में, भारत की स्वतंत्रता के अमृत-महोत्सव के अवसर पर आयोजित 'वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय कवि-सम्मेलन' को, विश्व के सर्वाधिक देशों के सबसे बड़े कवि-सम्मेलन के रूप में 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज किया जा चुका है। छह महाद्वीपों और इक्यावन देशों के पिचहतर कवियों ने इस कवि-सम्मेलन में एक साथ काव्य-पाठ कर यह विश्व-रिकॉर्ड बनाया था।

मनुमुक्त 'मानव' युवा शक्ति के प्रतीक ही नहीं, प्रेरणा-स्रोत भी थे। देहांत के एक दशक बाद भी उन्हें बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। परिवार ने मीडिया, सोशल मीडिया और फ़ेसबुक के माध्यम से उनकी प्रेरक स्मृतियों को जीवित रखा हुआ है। इसके लिए मनुमुक्त की बड़ी बहन और विश्वबैंक, वाशिंगटन डीसी (अमरीका) की वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ. एस अनुकृति का भी भरपूर सहयोग रहता है। अंत में मनुमुक्त की बैचमेट, भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और संप्रति धमतरी (छत्तीसगढ़) की जिलाधिकारी नम्रता गांधी के शब्दों में इतना ही कहा जा सकता है, ₹मनुमुक्त हमारे लिए बड़े भाई, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। उनके व्यक्तित्व में उत्तम हास्य का समावेश था, वहीं उनका दिल भी विशुद्ध सोने का बना था। उनके अंतर्मन में बड़ी गहराई थी, जिसका बाहर से अनुमान लगाना कठिन था। वह शानदार प्रशासक, स्वाभाविक नेता, श्रेष्ठ टीम-खिलाड़ी, सम्मानित वरिष्ठ, विश्वसनीय कनिष्ठ और सबके चहेते साथी तथा सहयोगी थे। हममें से किसी के लिए भी उन्हें भुला पाना संभव नहीं है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023